साप्ताहिक
शहर सत्ता
RNI TITLE CODE - CHHHIN17596
सोमवार, 05 मई से 11 मई 2025
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 10 में...
किसे सुनाएं दर्द भरी दास्तान...

पेज 12 में...
भ्रष्टाचार की भारतमाला...

वर्ष : 01 अंक : 09 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com
पेज 03 बस्तर होगा नक्सलमुक्त, विकास का बनेगा केन्द्र...

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कर रहा छत्तीसगढ़ की अनदेखी, शासन बेबस

गैरों पर करम... अपनों पर सितम...

- अंतरराज्यीय बस सेवा के लिए CG से करार को तैयार नहीं UP सरकार
- बिना अनुबंध के बेहिसाब किराया भाड़ा वसूल कर बेधड़क दौड़ रही हैं बसें

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

छत्तीसगढ़ राज्य से यात्री बसों के अनुबंध समझौते को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग तैयार ही नहीं है। बता दें कि छत्तीसगढ़ से उत्तरप्रदेश को छोड़कर महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, ओडिशा के सभी बड़े शहरों के लिए बस सेवा शुरू है। लेकिन उत्तर प्रदेश से कोई बस यहां नहीं आती बावजूद इसके छत्तीसगढ़ से तकरीबन 100 से ज्यादा यात्री बसें नियम विरुद्ध यूपी जा रही हैं। बता दें अविभाजित मध्यप्रदेश के समय उत्तरप्रदेश सरकार के साथ अंतरराज्यीय परमिट का अनुबंध हुआ था। उस वक्त अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र से छह बसें उत्तरप्रदेश के लिए चलती थीं।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अनुबंध टूट गया और बसें बंद करनी पड़ीं। उसके बाद से राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 रूट का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद उसका राजपत्र में प्रारंभिक प्रकाशन भी करा दिया था, लेकिन उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बता दें कि उत्तरप्रदेश में राज्य परिवहन निगम की बसें चलती हैं। यहां हाईवे पर केवल निगम के अलावा निजी बसें नहीं चल सकतीं। छत्तीसगढ़ जब मध्यप्रदेश से अलग हुआ तो यहां राज्य परिवहन निगम भंग कर दिया गया। यहां अब निजी बसें ही चलती हैं। यही वजह है कि उत्तरप्रदेश सरकार अपने राज्य में छत्तीसगढ़ की बसों के संचालन का अनुबंध नहीं कर पा रही।

बिना अनुबंध दौड़ रहीं बसें

उत्तरप्रदेश सरकार के साथ बस परमिट का करार नहीं हुआ है। अगर अनुबंध हो जाता तब छत्तीसगढ़ से उत्तरप्रदेश के 11 शहरों तक बसें चलेंगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, जशपुर से उत्तरप्रदेश के बनारस, इलाहाबाद, शक्तिनगर, रॉबर्ट्सनगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, अयोध्या, बलिया, मिर्जापुर, गाजीपुर और लखनऊ तक लक्जरी बसें नियमतयः चलने लगेंगी। फ़िलहाल रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से यूपी जाने वाली बसों को उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति नहीं है फिर भी बसें संचालित हैं।

यूपी के परिवहन अधिकारी का है यह कहना

"परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक प्राविधिक और प्रवक्ता अजीत सिंह का कहना है कि कई राज्यों के बीच रोडवेज की बसें संचालित हो रही हैं। हां यह जरूर है कि जम्मू कश्मीर, बिहार और छत्तीसगढ़ के लिए अब बसें संचालित नहीं हो रही हैं. नेपालगंज तक तो बस सेवा है, लेकिन काठमांडू की बस सेवा अब नहीं है।"

क्या कहती है नीति?

ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को केवल पर्यटक सेवा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, न कि रेगुलर रूट सेवा के लिए। यदि कोई बस राज्य से बाहर नियमित यात्रियों को लेकर जाती है और टिकट या बुकिंग करता है, तो यह क्लासिक केस ऑफ मिसयूज ऑफ परमिट माना जाएगा।

डीजल पर सब्सिडी का दुरुपयोग

जानकारों के अनुसार छत्तीसगढ़ में डीजल पर लगभग 23 % वैट है, जबकि यूपी में यह दर 12% है। इतना ही नहीं, यूपी सरकार अपने पंजीकृत परिवहन वाहनों को डीजल पर अतिरिक्त सब्सिडी भी देती है। इन टूरिस्ट बसों को यूपी में स्थानीय वाहनों के साथ खड़ा कर डीजल भरवाया जा रहा है और संबंधित डीलरों से रियायतें ली जा रही हैं। यह राज्य की सब्सिडी नीति का स्पष्ट उल्लंघन है।

सीधी बात

डी. रविशंकर, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर

■ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच अनुबंध क्यों नही हुआ ?

■■ अनुबंध के लिए मध्यपरिषद में बातें रखी जा चुकी है, इस पर पहल जारी है। अनुबंध में विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में अब भी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें संचालित है जबकि यहां निजी बसें चल रही है। दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक करार के लिए निजी बसों और स्टेट ट्रांसपोर्ट के बसों के लिए दूरी और टैक्स का निर्धारण करना होता है यह अब तक हुआ नही है, इसलिए यह अनुबंध नही हो पाया है।

■ अगर अनुबंध हुआ है तो किन मार्गों और कितने रुट के लिए ?

■■अनुबंध के लिए हमारी लगातार कोशिश जारी है पहले से हमने अनुबंध के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को प्रयागराज, अयोध्या जैसे बड़े शहरों के नाम दिए हैं अगर यह अनुबंध होता है इन प्रमुख शहरों पर छत्तीसगढ़ की निजी बसें चलेंगी।

■ यूपी सरकार से करार नही हुआ है तो छत्तीसगढ़ से बसें किन नियमों के तहत जा रही हैं ?

■■छत्तीसगढ़ से अभी जो बसें चल रही है वह ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी) परमिट पर चल रही है, अवैध रूप से किसी भी बस का संचालन नही होता है।

■ ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर यात्रि बसों का संचालन क्या सही है?

■■नहीं यह सही नहीं है, इससे राज्य के राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन, छत्तीसगढ़ से सैकड़ों यात्रि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सीधे बसों से ही जाते हैं, और एआईटीपी की बसें ही इनके लिए सहारा है।

राज्य के बड़े उद्योगपति-ट्रांसपोर्टर्स उत्तर प्रदेश और गुजरात से खरीद रहे हैं डीजल

डेढ लाख लीटर डीजल बाहरी राज्यों से खरीदने पर हो रही थी 300 करोड़ की राजस्व क्षति

टैक्स की छूट हासिल करने के लिए कारोबारी बल्क में डीजल यूपी से ले लिया करते थे। डीजल पर टैक्स घटा..लेकिन पब्लिक को कोई फायदा नहीं। छत्तीसगढ़ में कारोबारियों को फायदा पहुंचाने 7% टैक्स घटाया; 6 रुपए/लीटर कम में मिलेगा पैसे वालों को डीजल। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक उपयोग के लिए डीजल पर वर्तमान में 17% वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) लगता है। यह पहले 23% था, जिसे घटाकर 17% कर दिया गया था।

छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

डीजल के दामों में पैसे वालों को 6 रुपए का मुनाफा

राज्य में लगने वाले 24 प्रतिशत टैक्स के साथ डीजल इस वक्त 93 से 94 रुपए प्रति लीटर के आसपास मिलता है। अब इसमें 17 पर्सेंट टैक्स लगने की वजह से डीजल के दामों में करीब 6 रुपए की कमी आएगी।

आम पब्लिक के बदले बड़े सप्लायरों को मिल रहा फायदा

छत्तीसगढ़ सरकार के टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सड़क परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे, नहर, बांध या अन्य सिंचाई कार्यों से जुड़े, पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति, वॉटर ट्रीटमेंट, सीवरेज, कंस्ट्रक्शन, पुल, सुरंग, टर्मिनल बनाने, खनन के काम से जुड़े या खनन कारखाने की सामग्री का परिवहन करने वाले व्यापारियों को इसका फायदा मिलेगा।

यहां से खरीदने पर मिलेगी छूट

यह फायदा लेने के लिए व्यवसायियों के पास कैटेगरी B का पेट्रोलियम उत्पाद बल्क स्टोरेज लाइसेंस होना चाहिए। कारोबारी को सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही कम से कम 12 लीटर डीजल खरीदना होगा। कारोबारी सिर्फ इंडियन ऑयल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नायरा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से ही थोक में डीजल लेने पर इस छूट के हकदार होंगे।

ऐसा क्यों किया गया

सरकार के पास ये इनपुट था कि राज्य में लगभग डेढ़ लाख लीटर डीजल बाहरी राज्यों से खरीदी जाती थी, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। नए नियमों के तहत, बल्क में डीजल खरीदने पर 17 फीसदी टैक्स लिया जाएगा, जिससे बाहरी डीजल की खरीद पर रोक लगेगी। टैक्स की छूट हासिल करने के लिए कारोबारी बल्क में डीजल यूपी से ले लिया करते थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने डीजल पर वैट 23% से घटाकर 17% कर दिया है। शासन का उद्देश्य बड़े पैमाने पर डीजल की खरीद को प्रोत्साहित करना और राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होने से रोकना है। क्योंकि यह माना जाता है कि बहुत सारा डीजल उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत अन्य राज्यों से खरीदा जाता था।

पूर्व गृहमंत्री ने किया पांच साल में 10 हजार करोड़ के जीएसटी घोटाले का राजफाश

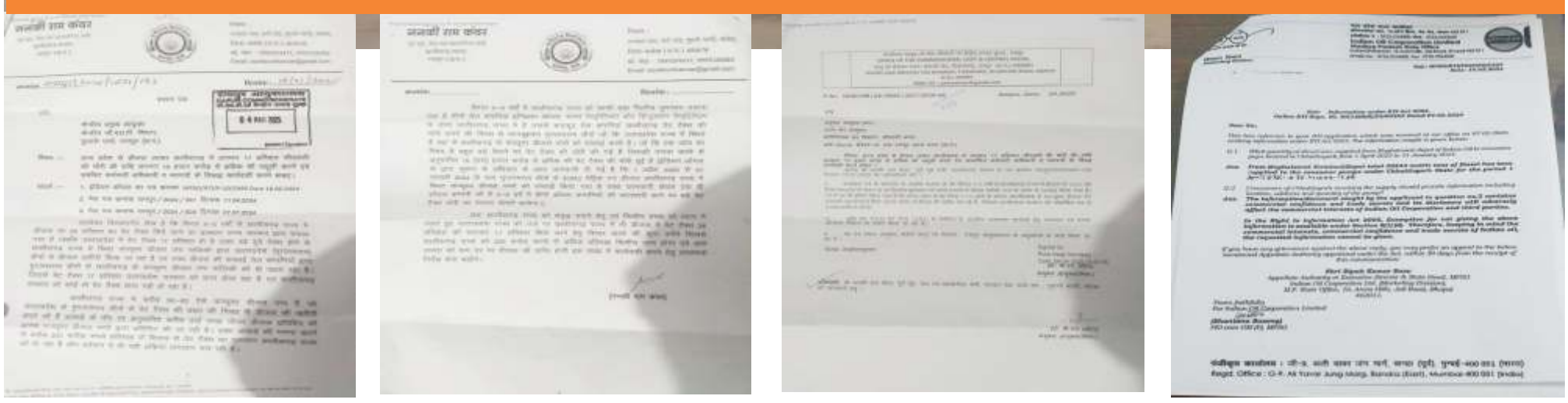

बस्तर होगा नक्सलमुक्त, विकास का बनेगा केंद्रः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर (शहरसत्ता)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि आगामी वर्षों में यह क्षेत्र राज्य का सबसे उन्नत, समृद्ध और पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक क्षेत्र बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के अंतर्गत मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र के संयुक्त प्रयासों से नक्सल विरोधी अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 15 महीनों में 1300 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो सरकार की पुनर्वास नीति की सफलता का प्रतीक है।

बस्तर को मिलेगा विकास का नया आयाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल उन्मूलन के पश्चात बस्तर क्षेत्र में लघु वनोपज प्रसंस्करण, पशुपालन, पर्यटन तथा अन्य संसाधन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए होमस्टे योजनाओं को बढ़ावा देना प्रारंभ किया है, जिससे स्थानीय आदिवासी समुदाय को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होगा। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 'नियद नेल्लनार' (आपका अच्छा गांव) योजना के अंतर्गत बस्तर के सुरक्षा शिविरों से सटे गांवों में 17 विभागों की 52 योजनाएं और 31 सामुदायिक सुविधाएं पहुँचाई जा रही हैं। इनमें सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन कार्ड एवं अन्य बुनियादी सेवाएं शामिल हैं।

बात के बदले बात, गोली के बदले गोली

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए सदैव प्रयासरत है, परंतु जो हिंसा का मार्ग चुनेंगे, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास नीति के तहत मुआवजा, भूमि और नौकरी जैसे लाभ दिए जा रहे हैं।

मौत के साए में विकास की दस्तक

गरियाबंद मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी माओवादी ढेर

गरियाबंद (शहर सत्ता)। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सघन जंगलों में एक बार फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक खतरनाक और वांछित नक्सली साकेत उर्फ योगेश उर्फ आयतु को ढेर कर दिया गया। यह माओवादी न केवल डिवीजन बॉडी कॉम्बैट का सक्रिय सदस्य था, बल्कि कई बड़े माओवादी नेताओं का अंगरक्षक भी रह चुका था। उस पर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इस कार्रवाई को माओवाद के खिलाफ राज्य की निर्णायक लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है।

बंदूक की भाषा को मिला करारा जवाब

एसपी निखिल राखेचा के अनुसार, ओडिशा की सीमा से सटे मोतीपानी के जंगलों में जब सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन पर थे, तभी माओवादियों ने घात लगाकर फायरिंग शुरू कर दी। सीआई-30, सीआरपीएफ और जिला बल की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में इस इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया। घटनास्थल से हथियार और दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिनसे माओवादी गतिविधियों को लेकर कई अहम सुराग मिल सकते हैं।

इनाम, डर और दहशत का हिसाब

माओवादियों के संगठनात्मक ढांचे में इनाम का निर्धारण उनकी भूमिका और अपराध के आधार पर होता है:

- 50 लाख–1 करोड़: पोलित ब्यूरो/सेंट्रल कमेटी
- 25 लाख: स्पेशल जोनल कमेटी
- 10 लाख: कंपनी कमांडर
- 8 लाख: डिवीजन कमेटी, बटालियन व प्लाटून प्रमुख
- 5 लाख व कम: स्थानीय कमांडर व सहयोगी सदस्य
- साकेत का मारा जाना इस बात का संकेत है कि राज्य माओवादी तंत्र की जड़ तक पहुंच रहा है।

दिल है लेकिन इलाज नहीं!

रायपुर कार्डियक इंस्टीट्यूट की बंद सर्जरी पर बोले सांसद बृजमोहन, 'गरीबों को मिल रही है सिर्फ तारीख पर तारीख'

रायपुर (शहर सत्ता)। राजधानी रायपुर के मेकाहारा परिसर स्थित कार्डियक इंस्टीट्यूट में इस समय मरीजों का ईलाज बंद है। एसकार्ट हार्ट एंड केयर सेंटर से अनुबंध खत्म होने के बाद राज्य सरकार कार्डियक इंस्टीट्यू के रूप में इसका संचालन कर रही है, लेकिन ओपीडी के अलावा फिलहाल यहां हृदय रोगियों की सर्जरी बंद है। इस हकीकत पर अब सियासत नहीं, संवेदनाएं उभर आई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र लिखकर इस 'निष्क्रिय जीवनरक्षक संस्थान' को दोबारा शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि गरीबों को इलाज के नाम पर बस अगली तारीख दी जा रही है, जिससे वे निजी अस्पतालों की महंगी फीस चुकाने के लिए घर-ज़मीन तक बेचने को मजबूर हैं।

"हृदय रोगियों के लिए नहीं धड़क रहा सिस्टम"

अपने पत्र में बृजमोहन ने लिखा —

"समय-समय पर अधिकारियों का ध्यान इस दिशा में आकर्षित किया गया, लेकिन आज भी हालात जस के तस हैं। मरीज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई की सांसें समय से पहले थम गईं, और जो बचे हैं, वे असहाय हैं।"

आशा की जगह इंतजार, इलाज की जगह तारीख

इस संस्थान में लंबे समय से हृदय रोगियों की सर्जरी सेवाएं ठप हैं। कार्डियोलॉजी यूनिट में उपकरण मौजूद हैं लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी, प्रशासनिक लापरवाही और बजट आवंटन की धीमी प्रक्रिया के चलते यह संस्थान सिर्फ एक इमारत बनकर रह गया है।

राज्य सरकार से की स्पष्ट कार्रवाई की अपील

बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम से आग्रह किया है कि वे खुद इस विषय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक करें और तत्काल निर्णय लें, जिससे यह संस्थान फिर से गरीबों के दिल की धड़कन बन सके।

जनता की नजर अब सरकार पर

इस पूरे मुद्दे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है —

"क्या छत्तीसगढ़ में गरीबों के दिल की सुनवाई सिर्फ कागज़ों पर होगी?"

एक ओर जहां सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को जनसुलभ बनाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की राजधानी में ही एक कार्डियक संस्थान बीमार पड़ा है।

संवेदनशीलता बनाम सिस्टम

इस मुद्दे ने राजनीति से ऊपर उठकर एक सामाजिक सवाल खड़ा कर दिया है। अगर जीवनरक्षक इलाज सिर्फ अमीरों के लिए रह जाएगा, तो क्या 'स्वस्थ छत्तीसगढ़' का सपना अधूरा नहीं रह जाएगा?

नगरीय विकास का खाका बनेगा 'नगर सुराज संगम'

5 और 6 मई को रायपुर में होगा जनप्रतिनिधियों से संवाद

रायपुर (शहर सत्ता)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो दिवसीय प्रबोधन कार्यशाला "नगर सुराज संगम" की मेज़बानी कर रही है, जिसमें प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यशाला का आयोजन 5 और 6 मई को होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल, रायपुर में किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य नगरीय विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करना है। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव 5 मई को करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समापन सत्र को 6 मई को संबोधित करेंगे।

संवाद के ज़रिए विकास की रूपरेखा

कार्यशाला के दौरान उप मुख्यमंत्री साव प्रत्येक नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद करेंगे। चर्चा का केंद्र बिंदु आगामी पांच वर्षों की विकास कार्ययोजना होगी। कार्यक्रम में शहरी शासन से जुड़े विभागीय प्रावधान, योजनाएं, बजटीय व्यवस्थाएं और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

साव की पाती से मिला आमंत्रण

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेशभर के महापौरों, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों को व्यक्तिगत पत्र लिखकर आमंत्रित किया है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा,

"जनता ने सुशासन की नीति पर भरोसा जताया है। यह कार्यशाला संकल्पों को दिशा देने का अवसर है।"

उन्होंने यह भी कहा कि सभी प्रतिनिधि अपने नगरों के प्रथम नागरिक हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़कर शहरों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्मार्ट बनाने की ज़िम्मेदारी निभानी होगी।

टीआरआई परिसर में बन रहा है सुसज्जित 100 सीटर हास्टल

रायपुर। आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए रायपुर आने पर अब प्रशिक्षण स्थल पर ही रूकने की व्यवस्था हो जाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आधुनिक सुख-सुविधाओं से युक्त 100 सीटर हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज निर्माणाधीन हॉस्टल का निरीक्षण किया और उन्होंने हॉस्टल परिसर में पेड़-पौधे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में लिफ्ट की भी व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए अधिकारियों को स्टीमेंट तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावास में मास्टर ट्रेनरों के लिए भी सुसज्जित कमरा बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। गौरतलब है कि नवा रायपुर स्थित आदिवासी अनुसंधान प्रशिक्षण परिसर में 5 करोड़ रूपए की लागत से 52 कमरे की सुसज्जित एवं सर्वसुविधायुक्त हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। हॉस्टल का निर्माण लगभग पूर्णतः की ओर है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

पूर्व अधिकारी ने हेल्थ मिनिस्टर को आखिर क्यों दी राधा-कृष्ण की काष्ठ प्रतिमा

शहर सत्ता/रायपुर/कोरिया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एक बार फिर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मंत्री जी के कोरिया ज़िले के खड़गवां स्थित घर में एक भव्य राधा-कृष्ण की मूर्ति भेंट में प्राप्त करते हुए देखा जा सकता है। यह मूर्ति सागौन की लकड़ी से बनी बताई जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपये है।

वीडियो में मंत्री जी के साथ दिखाई दे रहे व्यक्ति तत्कालीन स्वास्थ्य विभाग जगदलपुर के अधिकारी डॉ. केके नाग हैं। जानकारी के अनुसार, डॉ. नाग ने यह मूर्ति 2 फरवरी को सुबह-सुबह मंत्री जी के निवास पर पहुंचकर सप्रेम भेंट की। खास बात यह है कि डॉ. केके नाग ने कुछ सप्ताह पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले लिया है। सूत्रों का कहना है कि मंत्री जी डॉ. नाग के काम से बेहद प्रभावित हैं और उन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन (CGMSC) में एक बड़ी भूमिका देने की तैयारी चल रही है। इस घटनाक्रम ने स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आलोचकों का कहना है कि यदि यह नियुक्ति होती है, तो यह सत्ता और सेवा के बीच के नजदीकी रिश्तों की एक मिसाल होगी। हालाँकि, अब तक इस विषय पर मंत्री कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि विभागीय निर्णय पूरी पारदर्शिता के साथ लिए जाते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं विभाग की छवि पर सवालिया निशान छोड़ जाती हैं।

- **स्वास्थ्य मंत्री को पूर्व अधिकारी से भेंट में मिली 4 लाख की मूर्ति, मिल सकती है CGMSC में बड़ी भूमिका**

NEET UG परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के उतारे गए ताबीज रुद्राक्ष माला, काटे गए मौली धागे

शहर सत्ता/रायपुर। नीट को लेकर पिछले साल कई विवाद सामने आए थे। इसे देखते हुए इस बार खासा तैयारी की गई थी। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए थे। परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट को किसी प्रकार की मैटलिक आयटम जैसे ज्वेलरी, कड़ा, पहनकर आने वाले छात्रों को सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया।

परीक्षा केंद्र में स्टूडेंट्स को सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश करना था। परीक्षा के लिए जिसने आवेदन किया था, वहीं परीक्षा में बैठ रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए एआई की मदद ली गई। इसकी मदद से आवेदन में लगाए गए फोटो, परीक्षा केंद्र में लिए गए फोटो और सीसीटीवी फुटेज से 15 मिनट के फोटो का मिलान किया गया। प्रदेश में इस बार सिर्फ सरकारी संस्थानों में ही परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। देश भर में NEET UG 2025 की परीक्षा आज आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ में इस बार सिर्फ सरकारी संस्थानों को ही एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। रायपुर में 27 एग्जाम सेंटर बनाए गए। जहां जिले के 9300 कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए। वहीं, पूरे प्रदेश में 45 हजार स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी। सेंटर में सीसीटीवी कैमरे, जैमर और बायोमैट्रिक अटेंडेंस की मशीन लगाई गई थी। एग्जाम सेंटर में प्रवेश से पहले बच्चों की चेकिंग की गई। हाथ में बंधे धागे, ताबीज और रुद्राक्ष माला को भी उतरवाया गया। एग्जाम सेंटर में सिर्फ ट्रांसपेरेंट बॉटल ही अलाउड है। ज्यादातर कैंडिडेट लोअर और हाफ टी-शर्ट, शर्ट में एग्जाम सेंटर पहुंचे।

पिछले साल इतने छात्र हुए थे शामिल

नीट यूजी 2024 में छत्तीसगढ़ से 43873 छात्र शामिल हुए। इनमें से 22344 यानी 50.92 प्रतिशत छात्रों ने क्वालिफाई किया था। बीते छह साल में ऐसा पहली बार है, जब इतनी संख्या में छात्रों ने यह परीक्षा पास की थी। 2023 में 41196 छात्रों में से 19610 (47.60 %) नीट क्वालिफाई करने में कामयाब रहे। इस तरह से बीते साल की अपेक्षा राज्य में नीट का रिजल्ट 3.32 प्रतिशत बढ़ा है।

कांग्रेस की 'संविधान बचाओ यात्रा' पर डिप्टी CM अरुण साव का तंज

इन लोगों को संविधान नहीं कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में 8 मई को कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही है। हाल ही में यात्रा की तैयारी को लेकर नेताओं ने बिलासपुर में बैठक भी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, देश में केंद्र सरकार संविधान को नुकसान पहुंचा रही है। इस वजह से संविधान यात्रा निकाली जाएगी।

इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि, कांग्रेस हमेशा संविधान का उल्लंघन करती है। यह एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है, जो संविधान का दुरुपयोग करती है। अब जब सत्ता से बाहर है, तो उन्हें संविधान बचाने की याद आ रही है। जब समय पड़ता है, तो देश का विभाजन करते हैं। जब सत्ता से बाहर होते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो जाति जनगणना का विरोध करते हैं। सत्ता से बाहर आते हैं तो उसका समर्थन करते हैं। इसीलिए संविधान बचाओ की बजाय, इन्हें कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए।

संविधान बचाओ यात्रा पर पीसीसी चीफ बैज बोले

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान को घर-घर लेकर जाएगी। संविधान बचाओ अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार द्वारा संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर किए जा रहे लगातार हमलों, प्रतिशोध की राजनीति, आर्थिक कुप्रबंधन और सामाजिक न्याय के प्रणालीगत हनन का मुकाबला करना है। यह अभियान आम नागरिक की आवाज को बुलंद करेगा, जमीनी स्तर की चिंताओं को उजागर करेगा और हमारे संविधान में निहित मूल्यों पर फिर से जोर देगा। एआईसीसी सह-सचिव और सह-प्रभारी विजय जांगिड़ ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से हम संविधान की रक्षा करने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने और हम भारतीय के अधिकारों, सम्मान और भविष्य के लिये लड़ने के लिये एकजुट है।

फांसी के फंदे में लटकता मिला एम्स के जुनियर डॉक्टर का शव

रायपुर (शहर सत्ता)। राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां कार्यरत एक जूनियर डॉक्टर ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान डॉ. ए रवि (26 वर्ष) के रूप में हुई है, जो आंध्र प्रदेश के महबूबनगर के निवासी थे। जानकारी के अनुसार, डॉक्टर रवि ने 3 मई की रात अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। सुबह तक कोई हलचल न होने पर साथी डॉक्टरों को शक हुआ, जिसके बाद घटना की जानकारी अमानाका थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

नहीं मिला सुसाइड नोट, जांच जारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे आत्महत्या के कारणों पर फिलहाल स्पष्टता नहीं मिल पाई है। सीएसपी आजाद चौक अमन झा ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डॉक्टर के सहकर्मियों और परिचितों से पूछताछ की जा रही है।

सुशासन तिहार के तीसरे चरण के शुभारंभ पर क्विज 05 मई को

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेशभर में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन तिहार का तीसरा चरण 05 मई से 31 मई तक चलेगा, जिसमें आमजनों के लिए समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के शुभारंभ पर 05 मई, सोमवार को तेलीबांधा तालाब में शाम 6.30 बजे मनोरंजक गतिविधियों के बीच शासकीय योजनाओं से संबंधित क्विज, प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्रतिभागी नृत्य, गायन, कविता पाठ जैसी प्रतिभाओं की प्रस्तुति दे सकते हैं। विभिन्न स्पर्धाओं में जीतने वाले प्रतिभागियों को मौके पर ही डिस्काउंट-वाउचर, कूपन, उपहार दिया जाएगा।

जनजातीय संग्रहालय नवा रायपुर में बन कर तैयार

छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी विशिष्ट पहचान: नेताम

रायपुर। छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति की जीवंत झलक नवा रायपुर में देखने को मिलेगी। यह संग्रहालय लगभग बनकर तैयार हो चुका है। आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेताम आज इस संग्रहालय का निरीक्षण किया। यह ट्रायबल म्यूजियम छत्तीसगढ़ के जनजातीय जीवन शैली, संस्कृति एवं परंपरा पर आधरित है। एक ही छत के नीचे तैयार हो रहे म्यूजियम में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की संस्कृति एवं परंपरा से पर्यटक रूबरू हो सकेंगे। मंत्री श्री नेताम ने निरीक्षण के दौरान कहा कि संग्रहालय के मूर्त रूप में आ जाने के बाद निश्चित ही छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। जल्द ही आदिवासियों की जीवन शैलियों पर आधारित म्यूजियम पर्यटकों के लिए समर्पित होगा। इसकी तैयारी विभाग द्वारा की जा रही है। इस मौके पर विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर, टीआरआई के संचालक श्री जगदीश कुमार सोनकर, उप सचिव श्री बी.एस. राजपूत, कार्यपालन अभियंता श्री त्रिदीप चक्रवर्ती सहित विभागीय इंजीनियर और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि म्यूजियम के निर्माण में डिजिटल तकनीक एवं एआई की मदद ली जा रही है

संपादकीय

सुकांत राजपूत

'शब्द हिंसा'

वसीम बरेलवी लिखते हैं - कौन सी बात कहां, कैसे कही जाती है। वो सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ऐसा लगता है कि टीवी न्यूज मीडिया ने यह मान लिया है कि शब्द हिंसा में ही उसकी मुक्ति है। बहुत आक्रमक, बहुत बेलगाम। ऐसा प्रतीत होता है कि यह 'शब्द हिंसा' का समय है। यहां संवाद नहीं है, बातचीत भी नहीं है। विवाद और वितंडावाद है। यह किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का संवाद नहीं है, आक्रामकता का वीभत्स प्रदर्शन है। चीखते-चिल्लाते और दलों के प्रवक्ताओं को मुर्गो की तरह लड़ाते हमारे एंकर सब कुछ स्क्रीन पर ही तय कर लेना चाहते हैं। चीखते-चिल्लाते और दलों के प्रवक्ताओं को मुर्गो की तरह लड़ाते हमारे एंकर सब कुछ स्क्रीन पर ही तय कर लेना चाहते हैं।

मीडिया के इस जाल को तोड़ने की भी कोशिशें नदारद हैं। वस्तुनिष्ठता से किनारा करती मीडिया बहुत खौफनाक हो जाती है। निजी जीवन में बेहद आत्मीय राजनेता, एक ही कार में साथ बैठकर चैनल के दफ्तर आए प्रवक्तागण स्क्रीन पर जो दृश्य रचते हैं, उससे लगता है कि हमारा सार्वजनिक जीवन कितनी कड़वाहटों और नफरतों से भरा है। किंतु स्क्रीन के पहले और बाद का सच अलग है। बावजूद इसके हिंदुस्तान का आम आदमी इस स्क्रीन के नाटक को ही सच मान लेता है। लड़ता-झगड़ता हिंदुस्तान हमारा 'सच' बन जाता है।

हमारी मीडिया प्रेरणाएं क्या हैं? हम कहां से शक्ति और ऊर्जा पा रहे हैं। हमारा संचार क्षेत्र किन मानकों पर खड़ा है। पश्चिमी मीडिया के मानकों के आधार पर खड़ी हमारी मीडिया के लिए नकारात्मकता, संघर्ष और विवाद के बिंदु खास हो जाते हैं। जबकि संवाद और संचार की परंपरा में संवाद से संकटों के हल खोजने का प्रयत्न होता है। हमारी परंपरा में सही प्रश्न करना भी एक पद्धति है। सवालों की मनाही नहीं, सवालों से ही बड़ी से बड़ी समस्या का हल खोजना है, चाहे वह समस्या मन, जीवन या समाज किसी की भी हो।

यह कहना आजकल बहुत फैशन में है कि इस दौर में हर व्यक्ति पत्रकार है। हर व्यक्ति फोटोग्राफर है। हर व्यक्ति कम्युनिकेटर, सूचनादाता, मुखबिर हो सकता है, वह पत्रकार कैसे हो जाएगा? मेरे पास कैमरा है, मैं फोटो ग्राफर कैसे हो जाऊंगा। विशेष दक्षता और प्रशिक्षण से जुड़ी विधाओं को हल्का बनाने के हमारे प्रयासों ने ही हमारी मीडिया या संवाद की दुनिया को बहुत बड़ा नुक्सान पहुंचाया है। यह वैसा ही है जैसे कपड़े प्रेस करने वाले या प्रिंटिंग प्रेस वाले अपनी गाड़ियों पर 'प्रेस' का स्टिकर लगाकर घूमने लगें। मीडिया में प्रशिक्षण प्राप्त और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बिना आ रही भीड़ ने अराजकता का वातावरण खड़ा कर दिया है। लोकमान्य तिलक,महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, बाबासाहेब आंबेडकर, पं.जवाहरलाल नेहरू, मदनमोहन मालवीय, माधवराव सप्रे जैसे उच्च शिक्षित लोगों द्वारा प्रारंभ और समाज के प्रति समर्पित पत्रकारिता वर्तमान में कहां खड़ी है। भारत सरकार के आग्रह पर प्रेस कौंसिल आफ इंडिया ने पत्रकारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के निर्धारण के लिए एक समिति भी बनाई थी, बाद में उस कवायद का क्या हुआ पता नहीं।

देखा जाए तो समाज में फैली अशांति, स्पर्धा, लालसाओं और संघर्ष के बीच विचार के लिए सकारात्मक मुद्दे उठाने ही होंगे। मीडिया खुद अशांत है और गहरी स्पर्धा के कारण सही -गलत में चुनाव नहीं कर पा रहा है। ऐसे में मीडियाकर्मियों की जिम्मेदारी है कि खुद भी शांत हों और संवाद की शुचिता पर काम करें।

कोंदा-भैरा के गोठ

एक डहार केंद्र सरकार ह जम्मो पाकिस्तानी नागरिक मनला हमर देश ले तुरते जाए के आदेश जारी करे हे, उहें छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री ह वो मनला नागरिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता देके के सबर दिन बर इहें रहे के रद्दा बनाए के बात करत हे जी भैरा.

अच्छा..त राज्य सरकार ह केंद्र सरकार के आदेश ल ठेंगा देखाय असन करत हे का जी कोंदा?

कोन जनी संगी.. फेर मोला तो ए ह हम छत्तीसगढ़िया मन संग दोगलई करे बरोबर जनावत हे.. अरे भई हिंदू होवय चाहे फिंदू हमर बर तो सिरिफ वो मन परदेशिया यें.. जे मन अतका दिन ले राहत म घलो इहाँ के भाखा संस्कृति ल आत्मसात नइ करे हें.

सही आय जी.. फेर ए मन जेन कहिथें के वो मनला पाकिस्तान म अल्पसंख्यक होय के सेती प्रताड़ित करे जाथे त ए बात ह कइसे प्रमाणित हो सकथे के उन सही म प्रताड़ित हें, जबकि इहाँ ए मन हमर मन जगा ए शेखी बघारत रहिथें के पाकिस्तान के पूरा व्यापार जगत ह हमर मन के हाथ म रिहिसे.

कहूँ ए सब ह कथित हिंदू वोटबैंक ल बढ़ाए अउ खुश करे के उदिम तो नइ होही संगी?

अक्ती हमर किसानी के नवा बछर

सुशील भोले

छत्तीसगढ़ म जेन अक्ती के परब मनाए जाथे, वो ह किसानी के नवा बछर के रूप म ही मनाए जाथे. पुतरा-पुतरी के बिहाव या ए दिन बर-बिहाव खातिर शुभ मुहूर्त संग अउ कतकों अकन जुड़े मान्यता मन ओकर सहायक परंपरा के अंग आय, जे मन आने-आने क्षेत्र ले आए लोगन संग इहाँ आ के सॉझर-मिंझर होवत गे हवंय.

हमर इहाँ अक्ती के दिन जेन सबले बड़का परंपरा के निर्वाह करे जाथे ओला हमर महतारी भाखा म 'मूठ धरना' कहिथन. ए मूठ धरई ह असल म अपन-अपन खेत म खरीफ के नवा फसल खातिर बीजा बोवई के शुरुआत आय.

ए बीज बोए के परंपरा ल पूरा करे खातिर गाँव के सबो किसान अपन-अपन घर ले धान लेके एक निश्चित जगा सकलाथें. कोनो कोनो गाँव म ठाकुर देव या ठाकुर दिया म सकलाथें त कोनो गाँव म अउ कोनो मेर, जिहां वो गाँव के बइगा ह सबो झन के बिजहा ल संघार के पूजा पाठ करथे, मंत्र के माध्यम ले अभिमंत्रित करथे. तहाँ ले सबो किसान मनला वो अभिमंत्रित धान के बिजहा ल बाँट दिए जाथे. किसान मन इही अभिमंत्रित धान के बिजहा ल अपन खेत म लेग के बोवाई करथें.

कतकों गाँव मन म बइगा के द्वारा बिजहा के धान ल अभिमंत्रित करे के परंपरा नइ देखे म आवय. तब अइसन गाँव के किसान मन अपन खेत म ओनारे बर रखे धान के बिजहा ल अपन कुल देवता, ग्राम देवता आदि मन म समर्पित करत खेत डहार जाथे अउ जतका बिजहा बाँच जथे वो मनला खेत म बो देथे. ए किसम 'मूठ धरे' के परंपरा संपन्न हो जाथे.

अक्ती परब के दिन ही संझौती बेरा गाँव के सब किसान अउ पौनी पसारी संग कमइया मन कोनो चउंक-चाकर जगा म सकलाथें, जिहां अपन-अपन सामरथ के मुताबिक सौंजिया, पहाटिया, मरदनिया, धोबी आदि मन के नवा बछर खातिर नियुक्ति करथें. जे सौंजिया, कमइया अउ पौनी पसारी मन अपन जोंगे धान-पान अउ रुपिया पइसा के मुताबिक ठाकुर मन ले हुंकारू पा जाथें, ते मन अपन-अपन ठाकुर के पॉव-पैलगी कर के चोंगी-माखुर पीयत बुता-काम ल लग जाथें.

ए सब के संग ही अक्ती के दिन ले कतकों नवा कारज जइसे नवा करसी म पानी पीए के, आमा जइसन मौसमी फल ल टोरे अउ खाए के शुरुआत घलो करथें.

नान-नान नोनी मन बर ए ह पुतरा-पुतरी के बिहाव के मयारुक बेरा होथे. अक्ती के आगू दिन संझौती बेरा बने बाजा-रूंजी संग चुलमाटी के नेंग करे रहिथें, तेला ए दिन मड़वा ठउर म लानथें तहाँ ले तेल, हरदी मायन, बरात परघनी आदि सबो नेंग ल पूरा करत टिकावन करथें, पुतरा-पुतरी के बिहाव ल संपन्न करथें.

अक्ती के दिन ढाबा भरे के घलो परंपरा हे. ए दिन किसान मन अपन-अपन अंगना म गोबर के तीन ठक खंचवा बनाथें. इही गोबर ले बने खंचवा ल ढाबा कहे जाथे.

फेर ए ढाबा म एक म धान दूसर म ओन्हारी जइसे- तिंवरा या राहेर अउ तीसर म पानी भरे जाथे बने टिपटिप ले.

ढाबा म धान ओन्हारी अउ पानी भरे के बाद फेर ओकर आगू म हूमधूप देके पूजा करे जाथे. तेकर पाछू फेर बिजहा बोनी के टुकना म बीजहा, कुदारी, आगी पानी अउ हूमधूप धर के खेत म बोवई के मूठ धरे जाथें.

अक्ती के दिन घर के देवाला म नवा फल ल नवा करसी के पानी खातिर चढ़ाए जाथे. अपन पुरखा मनला सुरता कर के तरिया या नदिया म उरई के पौधा (घास) गड़िया के नवा करसी या तांबा के चरू म पानी डारथें. अपन पुरखा मनला पानी दिए जाथे, जइसे पितर तरपन म करे जाथे.

ए किसम सब अपन अपन परंपरा अउ मान्यता के मुताबिक अक्ती परब ल मनाथें.

अक्ती आगे घाम ठठागे चलव जी मूठ धरबो
अपन किसानी के शुरुआत सुम्मत ले सब करबो
बइगा बबा पूजा कर के सबला पहिली सिरजाही
फेर पाछू हम ओरी-ओरी बिजहा ल ओरियाबो

कुंवर रत्न भूषण सिंह, श्याम नगर रायपुर

मैं भी काश राम हो पाता

वचन पिता का एक निभाने, राजपाठ का मोह भूलाता,
राजा-रंक तो आने-जाने, जन-मानस के हृदय समाता,
मैं भी काश राम हो पाता।।

ऐसा त्याग कहाँ से लाता? कैकयी को भी माँ ही बताता,
सबसे पहले सबसे आगे, माँ-बेटे का प्रेम रमाता,
मैं भी काश राम हो पाता।।

पुष्प कमल का हो एक जैसे, शिव धनु उलटे हाँथ उठता,
पूर्ण नारी संगिनी श्रेष्ठ, जनक दुलारी वधु घर लाता,
मैं भी काश राम हो पता।।

सबरी के बेरों की खातिर, छप्पन भोग भी धुल बताता,
स्वर्ण-शूद्र का ताना-बाना, इनको कही राख कर आता,
मैं भी काश राम हो पाता।।

गंगा पार कराता मोहे, जो 'निषाद' मन घर कर जाता,
लेना-देना हुआ पुराना, इन सबसे ऊपर हो जाता,
मैं भी काश राम हो पाता।।

सीना चीर दिखता अपना, हनुमान सा संगी पाता,
देश-विदेश देख लो चाहे, भक्त ना दूजा ऐसा भाता,
मैं भी काश राम हो पाता।।

दुनिया जपति अमृत-अमृत, विष पीने में ध्यान लगता,
रोम-रोम में बसते शंकर, भोलेनाथ का भक्त कहाता,
मैं भी काश राम हो पाता।।

नाम मात्र से पत्थर तरते, सय्यम किन्तु तनिक न जाता,
राम शब्द है दो अक्षर का, भवसागर जो पार लगाता,
मैं भी काश राम हो पाता।।
मैं भी काश राम हो पाता।।

काम करो तो पूरा

केवल
"जातिगत जनगणना"
ही क्यों हो .....? ? ?

"जातिगत अपराधी"
की गणना हो..

"जातिगत करदाता"
की जनगणना हो..

"जातिगत सब्सिडी"
लेनेवालों की गणना हो..

"जातिगत टैक्स पेयर"
की गणना हो..

"जातिगत अंगदान"
करने वालों की गणना हो..

"जातिगत अंगदान"
प्राप्त करने वालों की गणना हो..

"जातिगत गुन्डागर्दी"
करने वालों की गणना हो..

"जातिगत समाज हित"
के कार्य करने वालों की गणना हो..

"जातिगत पत्थरबाजों "
की गणना हो..

मतलब....
जाति से संबंधित हर चीज की जातिगत जनगणना गहराई से हो.. हम सबको जानने क़ा अधिकार है की देशहित में और विकास में किसका क्या कितना और कैसा योगदान है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

सिख दंगों पर राहुल गांधी ने मांगी माफी, कहा- गलत हुआ

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में राहुल गांधी अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं. इवेंट के दौरान एक सिख छात्र ने राहुल गांधी से 1984 के दंगों और सिखों के मुद्दों पर कुछ सवाल भी पूछे.

छात्र ने राहुल गांधी से पूछा, "आपने कहा कि राजनीति निडर होनी चाहिए, डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ कड़ा पहनना नहीं चाहते, हम सिर्फ पगड़ी बांधना नहीं चाहते, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, जिसकी कांग्रेस पार्टी के शासन में अनुमति नहीं थी." छात्र ने कांग्रेस पर सिख आवाजों को अनसुना करने और 1984 के दंगों के आरोपी सज्जन कुमार जैसे लोगों को बचाने के भी आरोप लगाए.

राहुल गांधी ने दिया ये जवाब

इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी की कई गलतियां उस समय हुईं, जब वे वहां नहीं थे. उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के इतिहास में हुई हर गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं. राहुल गांधी ने आगे कहा, "मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 80 के दशक में जो हुआ वह गलत था. मैं कई बार स्वर्ण मंदिर गया हूं. भारत में सिख समुदाय के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं."

अमित मालवीय ने कसा तंज

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो शेयर कर राहुल गांधी पर तंज कसा है. उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, "एक युवा छात्र ने राहुल गांधी से कहा कि आपने सिखों के साथ अच्छा नहीं किया है और उन्हें उनकी पिछली अमेरिकी यात्रा के दौरान फैलाए गए कथित डर और भ्रम की याद दिलाई. अब राहुल गांधी को सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है."

मजिंदर सिंह ने साधा निशाना

राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। राष्ट्रीय सचिव मंजिंदर सिंह ने कहा, "अपनी दादी और पिता की तरह सिखों से..." जिसे राहुल गांधी के परिवार के इतिहास और सिख समुदाय के साथ उनके संबंधों पर एक तीखा कटाक्ष माना जा रहा है। राहुल गांधी के बयान ने सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है। कुछ यूजर्स ने उनके इस बयान को सिख समुदाय के प्रति उनकी संवेदनशीलता का प्रतीक बताया, जबकि अन्य ने इसे 'मगरमच्छ के आंसू' करार दिया।

क्या भारत में गिरेगा सोवियत स्पेस क्राफ्ट?

नई दिल्ली। सोवियत संघ ने 31 मार्च 1972 को स्पेसक्राफ्ट Kosmos 482 को लॉन्च किया था. ये स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह की ओर रवाना किया गया था, अब लगभग 50 साल बाद पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने की कगार पर है. डच वैज्ञानिक और सैटेलाइट ट्रैकर मार्को लैंगब्रोक का कहना है कि यह एक असामान्य, लेकिन सुरक्षित घटना है. स्पेसक्राफ्ट का एक बड़ा हिस्सा, जो अब भी कक्षा में घूम रहा है, 10 मई के आसपास पृथ्वी से 242 किमी/घंटा) की रफ्तार से टकरा सकता है. Kosmos 482 को शुक्र ग्रह की सतह पर उतरने के उद्देश्य से भेजा गया था, लेकिन लॉन्च के दौरान तकनीकी खराबी – विशेष रूप से टाइमर की गलत कॉन्फ़िगरेशन के कारण यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं निकल सका. इस वजह से Kosmos नाम दिया गया. ये एक सोवियत प्रथा थी कि जब भी किसी भी मिशन को उसकी मूल योजना में असफलता मिलती और वह पृथ्वी की कक्षा में फंस जाता तो उसे Kosmos नाम दे दिया जाता. Kosmos 482 चार टुकड़ों में टूट चुका है, लेकिन लैंडिंग मॉड्यूल सबसे अहम है. कॉसमॉस 482 का मुख्य लैंडिंग मॉड्यूल लगभग 480-500 किलोग्राम भारी है. ये गोलाकार है, जिसका डायमीटर 1 मीटर है. अब ये 400 किमी नीचे आ गया है, जो अब धीरे-धीरे पृथ्वी के करीब आ रहा है।

53 साल बाद धरती पर वापसी कर रहा Kosmos 482

फ्रांस से 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत

नई दिल्ली। भारत ने अपनी नौसेना की समुद्री फायर-पावर को बड़ी छलांग देने के लिए फ्रांस से 26 अति आधुनिक राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया है। राफेल नौसैनिक विमानों की आपूर्ति हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमता को नया आयाम देगी। हिंद महासागर इलाके में चीनी नौसेना की सक्रिय और आक्रामक सामरिक मौजूदगी के मद्देनजर भारतीय नौसेना के हवाई बेड़े में राफेल को शामिल किया जाना शक्ति संतुलन रणनीति के लिहाज से अहम है।

भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हुए अंतर-सरकारी समझौते के तहत 26 समुद्री राफेल जेट की खरीद पर करीब 64000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें 22 राफेल जेट सिंगल सीटर और चार ट्विन-सीटर होंगे। भारत-फ्रांस के बीच हुए इस रक्षा खरीद समझौते की शर्तों के अनुसार भारतीय नौसेना को राफेल नौसैनिक लड़ाकू विमानों की आपूर्ति तीन साल बाद यानि वर्ष 2028 से शुरू होगी और अगले तीन सालों में सभी विमानों की आपूर्ति की जाएगी। इस हिसाब से फ्रांस वर्ष 2030 तक नौसेना को सभी 26 लड़ाकू राफेल जेट की आपूर्ति कर देगा। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू ने राफेल खरीद से जुड़े अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय में समुद्री मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव दिनेश कुमार और राफेल का निर्माण करने वाली फ्रांसीसी विमानन कंपनी डसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रैपियर के बीच खरीद अनुबंध पर औपचारिक रूप से सोमवार को नौसेना भवन में होगा।

ऑस्ट्रेलिया में एंथनी अल्बनीज लगातार दूसरी बार बने पीएम

कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया में एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है. ऑस्ट्रेलिया में 2004 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटा है. अल्बनीज पिछले 21 साल में पहले ऐसे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें लगातार दूसरी बार पीएम बनने का मौका मिला है. चुनाव से पहले अल्बनीज ने विश्वास जताया था कि उनकी पार्टी को फिर से बहुमत मिलेगा. पांच सप्ताह के चुनाव अभियान के दौरान उनका प्रदर्शन विपक्षी नेता पीटर डटन से बेहतर रहा था. इस वजह से एंथनी अल्बनीज ने पीटर डटन को हरा दिया. इतना ही नहीं पीटर अपनी सीट भी हार गए. एंथनी अल्बनीज की राजनीतिक यात्रा काफी प्रेरणादायक रही है. अल्बानीज का बचपन काफी कठिनाईयों के साथ गुजरा था. वह सिंगर मदर चाइल्ड थे, जो विकलांगता पेंशन की मदद से अल्बनीज की देखभाल करती थीं।

सिंधु नदी के बाद अब बगलिहार बांध से रोका गया जल प्रवाह

नई दिल्ली। भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार बांध के माध्यम से पानी के प्रवाह को रोक दिया है और झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाने की योजना बना रहा है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि जम्मू के रामबन में बगलिहार जलविद्युत बांध और उत्तरी कश्मीर में किशनगंगा जलविद्युत बांध भारत को पानी छोड़ने के समय को रेगुलेट करने की क्षमता देते हैं।

भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद दशकों पुरानी संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। विश्व बैंक की मध्यस्थता से की गई सिंधु जल संधि ने 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपयोग को नियंत्रित किया है। बगलिहार बांध दोनों पड़ोसियों के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। पाकिस्तान इस मामले में विश्व बैंक की मध्यस्थता की मांग कर चुका है। पाकिस्तान को किशनगंगा बांध को लेकर भी खासकर झेलम की सहायक नदी नीलम पर इसके प्रभाव के कारण आपत्ति है। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है।

पीएम मोदी ने रविवार को वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह से मुलाकात की। इससे पहले पीएम मोदी ने नेवी चीफ से भी मुलाकात की थी।

तहव्वुर राणा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश

नई दिल्ली। देश को दहला देने वाले 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की गूंज एक बार फिर पटियाला हाउस कोर्ट की दीवारों से टकराई, जब उस हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. कोर्ट रूम में सन्नाटा पसरा था जब राणा की हैंडराइटिंग का नमूना लिया गया, एक ऐसा सबूत जो उसे खुद की ही जुबान से बेनकाब कर सकता है. NIA की सख्त निगरानी में राणा को कोर्ट लाया गया. मजिस्ट्रेट वैभव कुमार की उपस्थिति में जब राणा ने कागज पर कलम चलाई तो हर लकीर उसके अतीत की परतें खोलती नजर आई. जांच एजेंसी का मानना है कि उसके लिखावट और आवाज के नमूने कई गहरे राज खोल सकते हैं, जो अब तक अंधेरे में थे. तहव्वुर राणा फिलहाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की 12 दिन की रिमांड में है. इससे पहले उसने कोर्ट से अपने परिवार से बात करने की इजाजत मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

पहलगाम हमले में क्या खच्चर वालों ने की थी आतंकियों की मदद?

जिपलाइन ऑपरेटर्स के बाद अब NIA की जांच के घेरे में आए

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रोजाना जांच के दौरान नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं. फिलहाल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एनआईए की जांच के दौरान पहलगाम इलाके में खच्चर चलाने वाले कुछ लोग भी संदेह की घेरे में आए हैं. जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, पहलगाम आतंकी हमले में पहलगाम के कुछ खच्चर चलाने वालों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, उन्हें जल्द हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है. जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक. पहलगाम आतंकी हमले के बाद करीब 1500-2000 खच्चर चालकों से जांच एजेंसियों की पूछताछ लगातार जारी है.

आतंकियों के रूट मैप का पता लगाने की कोशिश

सूत्रों के मुताबिक. घटना के बाद से ही लगातार खच्चर चालकों से पूछताछ से यह रूट समझने की कोशिश की जा रही है कि कहां कहां एग्जिट प्वाइंट उस दुर्गम इलाके में है और किस जगह से घुसा जा सकता है. इसके ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश है कि आतंकी किस रास्ते से आए होंगे और कहां से वह फरार हुए.

शुरुआती जांच में क्या पता चला ?

शुरुआती जांच में कुछ खच्चर चालकों के बयानों में विरोधाभास भी पाया गया है और इसी वजह से जांच एजेंसी ऐसे खच्चर चालकों को संदिग्ध के तौर पर देख रही है. एनआईए की जांच एक तरफ जहां आतंकी हमले में आतंकी किस रूट से आए, किस तरह से फरार हुए, उसको लेकर तो चल ही रही है, साथ ही यह पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि क्या उनको स्थानीय लोगों का समर्थन था? अगर था तो वह कौन लोग हैं।

भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर पकड़ा गया PAK रेंजर

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है. पड़ोसी मुल्क के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है. इस बीच आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार (03 मई, 2025) को बताया कि राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया है. यह घटनाक्रम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच सीमा सुरक्षा बल के एक जवान को रेंजर्स की ओर से हिरासत में लिए जाने के करीब एक हफ्ते से ज्यादा समय के बाद हुआ है. इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे. उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी रेंजर को फोर्स के राजस्थान फ्रंटियर ने हिरासत में लिया है. वहीं, बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ को पाकिस्तानी रेंजर्स ने 23 अप्रैल को पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पकड़ा था।

पंजाब ने निकाली लखनऊ की हवा जीत के साथ पहुंचे दूसरे स्थान पर

धर्मशाला। पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 37 रनों से हरा दिया है. पंजाब की टीम ने पहले खेलते हुए 236 रन बनाए थे, जिसके जवाब में LSG की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 199 रन ही बना पाई और 37 रनों से मैच हार गई. पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन ने 91 रनों की तूफानी पारी खेली, वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने कहर बरपाते हुए 3 विकेट चटकाए. इस जीत के साथ पंजाब प्लेऑफ में जगह बनाने के बहुत करीब आ गई है.

धर्मशाला में खेले गए इस मैच में पंजाब किंग्स ने पहले खेलते हुए 236 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में लखनऊ टीम की शुरुआत बहुत खराब रही क्योंकि 16 के स्कोर तक दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे. एडन मार्करम ने 13 रन बनाए जबकि मिचेल मार्श का खाता तक नहीं खुल पाया. निकोलस पूरन लगातार पांचवें मैच में बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे क्योंकि पंजाब के खिलाफ भी वो सिर्फ 6 रन बना पाए. कप्तान ऋषभ पंत की खराब फॉर्म बदस्तूर जारी है, वो 17 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए. आलम यह था कि लखनऊ की आधी टीम 73 के स्कोर तक पवेलियन लौट चुकी थी. यहां से अब्दुल समद और आयुष बदोनी ने कमान संभालते हुए 81 रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन जब टीम जीत की ओर आगे बढ़ रही थी तब समद 24 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हो गए.

आयुष बदोनी अब भी क्रीज पर डटे हुए थे, लेकिन जब तक उन्होंने तेज रफ्तार से शॉट्स लगाने शुरू किए तब तक बहुत देर हो चुकी थी. उन्होंने 40 गेंद में 74 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 5 चौके और 5 छक्के निकले. आलम यह था कि LSG को आखिरी ओवर में जीत के लिए 49 रन बनाने थे. इस बड़ी हार के कारण लखनऊ की प्लेऑफ की राह बहुत कठिन हो गई है. पंजाब की इस जीत में सबसे बड़ा योगदान प्रभसिमरन सिंह और अर्शदीप सिंह का रहा. प्रभसिमरन ने बैटिंग में 91 रन की पारी खेल पंजाब को 236 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की. वहीं अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए. इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में पंजाब 15 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर आ गई है.

रोमांचक मैच में एक रन से जीती केकेआर

कोलकाता। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को एक रन से हराया। केकेआर और राजस्थान के बीच यह मुकाबला बेहद करीबी रहा और आखिरी में कोलकाता में टीम महत्वपूर्ण जीत दर्ज करने में सफल रही। केकेआर ने इस तरह प्लेऑफ के लिए अपनी उम्मीदें कायम रखी है। केकेआर ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और आंद्रे रसेल की तूफानी पारी की मदद से 20 ओवर में चार विकेट पर 206 रन बनाए। जवाब में राजस्थान के लिए कप्तान रियान पराग ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 205 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 71 रन के स्कोर पर पांच विकेट गंवा दिए। इसके बाद रियान पराग ने शिमरॉन हेटमायर के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की और टीम को मुश्किल से उबारा। रियान ने इस दौरान मोईन अली के ओवर पर लगातार पांच छक्के लगाए। इस साझेदारी को हर्षित राणा ने हेटमायर को आउट कर तोड़ा जो 29 रन बनाकर आउट हुए। इसके कुछ देर बाद हर्षित ने रियान को भी अपना शिकार बनाया। रियान शतक पूरा नहीं कर सके और 95 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

CNG गाड़ी चलाने के लिए खर्च करने होंगे ज्यादा पैसै

नई दिल्ली। अगर आप अपनी गाड़ी में CNG का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने एक बार फिर CNG की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. यह बढ़ोतरी 3 मई, सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी हैं. राजधानी दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, कानपुर और मेरठ जैसे कई बड़े शहरों में CNG अब महंगी हो गई है. दिल्ली में अब CNG की नई कीमत 77.09 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो पहले 76.09 रुपये थी. यानि उपभोक्ताओं को हर किलो CNG पर अब 1 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे. इससे पहले 7 अप्रैल को भी IGL ने दिल्ली में CNG के दाम में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की थी. यानि सिर्फ एक महीने में दूसरी बार दाम बढ़ाए गए हैं.जानकारों का मानना है कि लगातार हो रही यह बढ़ोतरी आम जनता की जेब पर सीधा असर डाल रही है. विशेषकर उन लोगों के लिए जो रोजाना CNG पर निर्भर रहते हैं. जैसे कैब ड्राइवर, ऑटो चालक और कमर्शियल वाहन मालिक।

प्लेऑफ का फंसा पेंच, पंजाब किंग्स ने पाक से बुलाया तूफानी ऑल राउंडर

नई दिल्ली। IPL 2025 के बीच पंजाब किंग्स ने बहुत बड़ा फैसला लिया है. ग्लेन मैक्सवेल चोट के कारण बाकी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, PBKS मैनेजमेंट ने मैक्सवेल को घातक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल ओवेन से रिप्लेस किया है. इंडियन प्रीमियर लीग ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से यह जानकारी दी है. ओवेन अभी पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जाल्मी के लिए खेल रहे हैं, बताते चलें कि PSL 2025 का समापन 11 मई को होने वाला है.

मिचेल ओवेन सबसे पहले बिग बैश लीग में दमदार प्रदर्शन के चलते चर्चा में आए थे. BBL 2025 के फाइनल मैच में उन्होंने 42 गेंद में 108 रनों की पारी खेल होबार्ट हरिकेन्स को खिताबी जीत दिलाई थी. हालांकि उन्हें IPL 2025 मेगा ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला था. अब मैक्सवेल के रिप्लेसमेंट के तौर पर पंजाब किंग्स ने ओवेन को 3 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है. मैक्सवेल की बात करें तो उंगली में चोट के कारण उन्हें आईपीएल 2025 के बाकी टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है. मिचेल ओवेन का आना पंजाब किंग्स की किस्मत बदल सकता है क्योंकि वो ना केवल तेज गेंदबाजी कर सकते हैं बल्कि मिडिल ऑर्डर के साथ-साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर भी मैदान में रंग जमा चुके हैं. ओवेन ने अब तक खेले 30 टी20 मैचों में बल्लेबाजी करते हुए 646 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शानदार शतकीय पारी भी शामिल हैं. इसके अलावा गेंदबाजी में भी उन्होंने 10 विकेट लिए हैं.

प्लेऑफ के करीब है पंजाब : पंजाब किंग्स अभी IPL 2025 की पॉइंट्स टेबल में 10 मैचों में 6 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है. पंजाब को अगर बिना किसी मुसीबत के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो उसे अपने बाकी 4 में से 2 मैच जरूर जीतने होंगे।

सैमसंग को 4400 करोड़ रुपये का टैक्स भरने का आदेश

नई दिल्ली। सैमसंग कंपनी को भारत में एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार ने सैमसंग पर 520 मिलियन डॉलर (करीब 4400 करोड़ रुपये) का टैक्स भरने का आदेश दिया है। सैमसंग कंपनी इस आदेश के खिलाफ लड़ रही है। कंपनी पर आरोप है कि उसने बाहर से मंगवाए गए नेटवर्किंग उपकरणों को गलत तरीके से दिखाया। सैमसंग का कहना है कि भारतीय अधिकारियों को इस बारे में पहले से पता था। सैमसंग का कहना है कि रिलायंस जियो ने भी ऐसे ही उपकरण बिना टैक्स दिए मंगवाए थे। सैमसंग का आरोप है कि रिलायंस ने उन्हें टैक्स के बारे में पहले से मिली चेतावनी के बारे में नहीं बताया। टैक्स और जुर्माने को मिलाकर सैमसंग को कुल 601 मिलियन डॉलर चुकाने पड़ सकते हैं। सैमसंग दूसरी बड़ी विदेशी कंपनी है जिसने हाल ही में भारत सरकार के टैक्स की मांग को चुनौती दी है। इससे पहले, फॉक्सवैगन ने भी सरकार पर मुकदमा किया था।

ITR भरने से पहले इन सेक्शंस के बारे में जान लें... 80C, 80D पर खास ध्यान दें

नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है. ये फॉर्म उन व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए हैं, जिनकी सालाना आय 50 लाख तक है. यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR भरने की प्रक्रिया अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है. ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे आयकर अधिनियम, 1961 के उन अहम सेक्शन्स को समझें जो टैक्स कैलकुलेशन, डिडक्शन और टैक्स रेजीम चुनने में मदद करते हैं.

पुराने टैक्स रेजीम के तहत डिडक्शन, 80C

अगर आप पुराना टैक्स सिस्टम अपनाते हैं, तो सेक्शन 80C आपके लिए बेहद फायदेमंद है. इसके तहत आप PPF, EPF, ELSS, टैक्स सेविंग FD और जीवन बीमा जैसे निवेश पर 1.5 लाख तक की छूट पा सकते हैं. लेकिन याद रखें, नए टैक्स रेजीम में यह छूट नहीं मिलती. हालांकि, नया रेजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स सेक्शन 80CCD(2) के तहत एनपीएस में एम्प्लॉयर की योगदान पर 10 फीसदी तक की छूट ले सकते हैं. होम लोन पर ब्याज, सेक्शन 24B अगर आपने घर के लिए लोन लिया है, तो उसके ब्याज पर आप 2 लाख तक की छूट ले सकते हैं और अच्छी बात ये है कि ये छूट दोनों टैक्स रेजीम में मिलती है.

HRA पर छूट, सेक्शन 10(13A)

अगर आप किराये के घर में रहते हैं और सालाना 1 लाख से ज़्यादा किराया देते हैं, तो HRA पर छूट पा सकते हैं. इसके लिए सेक्शन 10(13A) लागू होता है.

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट, सेक्शन 80D

स्वास्थ्य बीमा पर भी टैक्स में बड़ी राहत मिल सकती है. सेक्शन 80D के तहत आप सालाना 1 लाख तक की छूट ले सकते हैं. अगर आपकी उम्र 60 से कम है, तो 25,000 तक की छूट मिलेगी, लेकिन सीनियर सिटिज़न के लिए यह सीमा 50,000 तक है.

डॉलर से भर गया भारत का खजाना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने किया कमाल

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार 25 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में 1.98 बिलियन डॉलर बढ़कर 688.13 बिलियन पर पहुंच गया है. यह लगातार आठवां हफ्ता है जब भारत के रिजर्व में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि, ये आंकड़ा अब भी सितंबर 2024 के 704.88 बिलियन डॉलर के ऑल-टाइम हाई से थोड़ा नीचे है, लेकिन ट्रेंड देखकर साफ है कि भारत की फॉरेन करंसी पोजिशन फिर से मजबूत हो रही है. इस बढ़त के पीछे सबसे बड़ा योगदान Foreign Currency Assets (FCA) का रहा, जो 2.17 बिलियन डॉलर बढ़कर 580.66 बिलियन डॉलर हो गए हैं. ध्यान दें, FCA में डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और येन जैसी दूसरी मुद्राएं भी शामिल होती हैं और उनकी वैल्यूएशन से भी इसमें उतार-चढ़ाव आता है. हालांकि, इस हफ्ते सोने के भंडार में 207 मिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है और अब यह 84.36 बिलियन डॉलर पर आ गया है. इसके अलावा IMF से जुड़े Special Drawing Rights (SDRs) 21 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.58 बिलियन डॉलर हो गए, और IMF में भारत की रिज़र्व पोजिशन भी 2 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.51 बिलियन डॉलर हो गई.

केंद्र के पास कोई उधारी नहीं

RBI ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के पास उनकी कोई उधारी नहीं है, लेकिन राज्यों को दिए गए लोन में गिरावट आई है. ये 36,792 करोड़ से घटकर 22,324 करोड़ हो गया है. अगर हम मार्च 2025 से अब तक की बात करें, तो भारत के फॉरेक्स रिज़र्व में कुल 19.80 बिलियन डॉलर यानी 1.67 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है. इसमें FCA, गोल्ड, SDR और IMF पोजिशन, सभी ने सकारात्मक योगदान दिया है.

साप्ताहिक शहर सत्ता

8 मई को बिलासपुर में होगी कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली

बिलासपुर संभाग के नेताओं की बैठक में रैली की रणनीति की गई तय

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश में कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरूआत बिलासपुर से होगी। 8 मई को बिलासपुर में संविधान बचाओ रैली होगी, उसके बाद सभी जिला मुख्यालयों और विधानसभा क्षेत्रों में संविधान बचाओ रैली निकाली जायेगी। जिला एवं विधानसभा के बाद कांग्रेस घर-घर तक संविधान बचाओ अभियान लेकर जायेगी।

बिलासपुर में होने वाली संविधान बचाओ रैली की तैयारी के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और एआईसीसी सह-सचिव एवं प्रदेश सह-प्रभारी विजय जांगिड़ ने बिलासपुर संभाग के पदाधिकारियों, विधायकों की बैठक लिया। बिलासपुर संभाग की रैली के लिए पूर्व मंत्री उमेश पटेल को कांग्रेस का संयोजक बनाया गया है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान को घर-घर लेकर जायेगी। उन्होंने कहा कि संविधान बचाओ अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार द्वारा संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर किये जा रहे लगातार हमलों, प्रतिशोध की राजनीति, आर्थिक कुप्रबंधन और सामाजिक न्याय के प्रणालीगत हनन का मुकाबला करना है। यह अभियान आम नागरिक की आवाज को बुलंद करेगा, जमीनी स्तर की चिंताओं को उजागर करेगा और हमारे संविधान में निहित मूल्यों पर फिर से जोर देगा।

एआईसीसी सह-सचिव एवं सह-प्रभारी विजय जांगिड़ ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से हम संविधान की रक्षा करने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों को बनाये रखने और हम भारतीय के अधिकारों, सम्मान और भविष्य के लिये लड़ने के लिये एकजुट है। हम इस देश के गरीबों को लिये अपनी लड़ाई में अडिग रहेंगे उनके अधिकारों की वकालत करेंगे और उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। बैठक में वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, पूर्व सांसद इंग्रिड मैक्लाउड, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, विधायकगण उमेश पटेल, फूलसिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, ब्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, शेषराज हरवंश, पूर्व विधायक मोतीलाल देवांगन, हृदय राम राठिया, शैलेष पाण्डेय, के.के. ध्रुव, थानेश्वर साहू, संजीत बनर्जी, महामंत्री प्रेमचंद जायसी, वासुदेव यादव आदि उपस्थित थे।

कांग्रेस की मुहिम का नतीजा जातिगत जनगणना- बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की मुहिम का नतीजा है जातिगत जनगणना। कांग्रेस पार्टी और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष किया। मोदी, शाह सहित आरएसएस और भाजपा के तमाम नेता हमारे जिस मांग को देश को बांटने की साज़िश बता रहे थे, जिस विषय में विपक्ष का उपहास उड़ाते थे, अब उसी विषय पर मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है। हमने पहले भी कहा कि ओबीसी इस देश का सबसे बड़ा वर्ग है, बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तौर पर विभिन्नताएं हैं।

जातिगत जनगणना किए बिना सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करना संभव ही नहीं है, सामाजिक न्याय के लिए यह अति आवश्यक कदम है। कांग्रेस की यह मांग है कि केवल जातिगत जनगणना को आगामी आम जनगणना में शामिल करने की घोषणा मात्र से काम नहीं चलेगा, जातिगत जनगणना करवा के तत्काल आंकड़े जारी करें सरकार।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में जातिगत जनगणना के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, इसी के चलते मोदी सरकार बाध्य हुई है। मोदी सरकार तो 2021 में होने वाली आम जनगणना को 4 साल से रोक रखा है, अंततः कांग्रेस के दबाव में जातिगत जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल करवाने को बाध्य हुई है।

पिछले तीन दशकों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के भी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र में रोज़गार में आरक्षण दिया जा चुका है। पर अभी भी हमें यह ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वो कौन-कौन सा समुदाय हैं जो आरक्षित वर्गों में आते हैं और उनकी जनसंख्या तथा असली हालात क्या हैं? सामाजिक न्याय को पूरी तरह से तभी स्थापित किया जा सकता है जब हमें इन समुदायों की जनसंख्या स्पष्ट रूप से पता हो। इसीलिए जाति की गिनती ज़रूरी है।

महंगाई के कारण जीएसटी संग्रहण में वृद्धि को उपलब्धि बता रहे हैं भाजपाई

अंग्रेजों से ज्यादा बेरहम है भाजपा की सरकार

रायपुर। अप्रैल 2025 में ज्यादा जीएसटी संग्रहण को सरकार की उपलब्धि बताए जाने पर कड़ा प्रतिवाद करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकारें आम जनता से कर वसूली करने में अंग्रेजों से भी ज्यादा बेरहम है। जीएसटी संग्रहण के कुल राशि को उपलब्धि बताने से पहले सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए की माल और सेवा के कुल मात्रा में वृद्धि हुई है या कमी?

जन विरोधी भाजपा सरकारों के द्वारा माल और सेवा के आंकड़ों को अपने मुताबिक प्रसारित करके प्रचारित किया जा रहा है, असलियत यह है कि सत्ता के संरक्षण में मुनाफाखोरी बढ़ी है जिसके कारण जो सामग्री 100 रुपए में मिला करती थी उसके दाम 120 से 125 तक हो गया है, इसी के कारण कुल कर संग्रहण की राशि अधिक दिख रही है। खपत की कुल मात्रा नहीं बढ़ी है लेकिन उतने ही सामग्री पर टर्नओवर और कर संग्रहण की राशि जरूर बढ़ गई है। भाजपा की सरकारें असल तथ्यों को छुपा कर अपने टैक्स टेरर से जनता पर किए जा रहे अत्याचार को उपलब्धि बताने में जुटे हैं।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले सीमेंट के दाम 225 रुपया प्रति बोरा था जिस पर 28 प्रतिशत की दर से लगभग 63 रुपए जीएसटी वसूली होती थी, आज इसी 50 किलो के एक बोरी सीमेंट का दाम 310 रुपए कर दिया गया है जिसके एवज में जीएसटी का कलेक्शन भी लगभग 87 रुपए हो रहा है, मतलब साफ है कि एक बोरी सीमेंट में ही पिछली साल की तुलना में इस वर्ष 24 रुपए अधिक जीएसटी वसूला जा रहा है।

इसी तरह से बाकी दैनिक आम उपभोग की वस्तुओं पर भी जीएसटी की वसूली में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दुध, दही, पनीर, आटा, मैदा, बेसन, सूजी, अनाज, दलहन, तिलहन से लेकर कफ़न के कपड़ों तक को इस सरकार ने जीएसटी के दायरे में ला दिया है। आम जनता की क्रय क्षमता नहीं बढ़ी, उत्पादन नहीं बढ़ा, खपत नहीं बढ़ी लेकिन उतने ही माल पर दाम अधिक होने के चलते जीएसटी का संग्रहण जरूर बढ़ गया है।

रायपुर नगर निगम में 7 मई से जोनवार होगा समाधान शिविर का आयोजन

पहला शिविर जोन 2 के शहीद स्मारक भवन में निर्धारित

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार "सुशासन तिहार 2025" के तहत नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। प्रथम चरण के अंतर्गत 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक सभी 10 जोनों में आमजन की मांगों एवं शिकायतों से संबंधित ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन प्राप्त किए गए। इसके बाद द्वितीय चरण में प्राप्त शिकायतों और मांगों का गुणवत्तापूर्ण समाधान तेजी से किया जा रहा है। अब सुशासन तिहार 2025 के तृतीय चरण में रायपुर नगर निगम द्वारा 7 मई से सभी 10 जोनों में सार्वजनिक स्थलों पर जोनवार समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में अधिकारीगण आवेदकों को उनके आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी देंगे तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करेंगे।

जोनवार समाधान शिविरों की तिथियां एवं स्थल निम्नानुसार हैं:

जोन 1: 10 मई – दही हांडी मैदान, गुढ़ियारी
जोन 2: 7 मई – शहीद स्मारक भवन, जीई रोड
जोन 3: 13 मई – बीटीआई ग्राउंड, शंकर नगर
जोन 4: 15 मई – सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम
जोन 5: 19 मई – डीडी नगर सामुदायिक भवन, सेक्टर-2
जोन 6: 20 मई – शहीद संजय यादव उच्चतर माध्यमिक शाला, टिकरापारा
जोन 7: 23 मई – पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, जीई रोड
जोन 8: 27 मई – सामुदायिक भवन, भारत माता स्कूल के सामने, टाटीबंध
जोन 9: 28 मई – इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कम्युनिटी हॉल, जोरा
जोन 10: 30 मई – सामुदायिक भवन, गुरुद्वारा, देवपुरी

श्रवण कुमार की तर्ज पर बुजुर्गों को तीर्थयात्रा- ओपी चौधरी

रायपुर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 800 तीर्थ यात्रियों को लेकर रायगढ़ से तीर्थ स्थल मथुरा एवं वृंदावन के लिए रवाना हुई। वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार श्रवण कुमार की परंपरा को अपनाकर प्रदेश के बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रही है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए खास है। क्योंकि हमारे रायगढ़, जशपुर एवं सारंगढ़ अंचल के तीर्थ यात्री मथुरा एवं वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हम सभी के परिवार के वृद्ध जनों की प्रबल इच्छा होती है कि वे अपने जीवन में तीर्थ यात्रा पर जाए।

श्रमिक दिवस पर विशेष : छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से श्रमिकों के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव

सुरक्षा और रोजगार की गारंटी के साथ बढ़ा महिला श्रमिकों का सम्मान

रायपुर। हर वर्ष 1 मई को हम श्रमिक दिवस मनाते हैं। यह एक ऐसा दिन जो श्रमिकों के अथक परिश्रम, संघर्ष और योगदान को सम्मान देने का अवसर प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संपदा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य की आर्थिक प्रगति में महिला श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाना जाता है।

कृषि, खनन, वनों से प्राप्त उत्पादों और छोटे उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में महिलाएँ खेती-बाड़ी, तेंदूपत्ता संग्रहण और हस्तशिल्प निर्माण जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य, घरेलू सेवाएँ और छोटे व्यापारों में उनकी भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। महिला श्रमिकों की भागीदारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में, फिर भी उनकी मेहनत को अब भी उचित मान्यता और पारिश्रमिक नहीं मिल पाता। महिला श्रमिकों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। जिनमें समान वेतन का अभाव, समान कार्य के बावजूद वेतन असमानता, खनन और निर्माण जैसे क्षेत्रों में असुरक्षित परिस्थितियाँ, प्रसूति लाभों और स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित पहुँच, कम पढ़ाई और तकनीकी प्रशिक्षण के कारण सीमित अवसर, पारंपरिक सोच और घरेलू जिम्मेदारियाँ उनकी स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिला श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिसमें मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए विशेष सहायता दी जा रही है। नई श्रमिक नीति द्वारा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिला श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी और कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को अनिवार्य बनाया गया है। महिला शक्ति केंद्रों के विस्तार से प्रत्येक जिले में महिला शक्ति केंद्र स्थापित कर महिला श्रमिकों को कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देकर महिला स्वावलंबन के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में पहला कदम

एनआईटी रायपुर ने किया रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए एमओयू

शहर सत्ता/रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर (एनआईटी रायपुर) ने जन्यु टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जो रोबोटिक्स, औद्योगिक स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक रणनीतिक साझेदारी को चिह्नित करता है।

इस समझौता ज्ञापन पर एनआईटी रायपुर के निदेशक प्रो.एन वी रमना राव और जन्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अभिमन्यु राजा द्वारा हस्ताक्षर किये गए | इस दौरान प्रोफेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, प्रो. श्रीश वर्मा, , डीन (कॉरपोरेट रिलेशन एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन) प्रो. एस सान्याल, हेड (करियर डेवलपमेंट सेंटर) प्रो.समीर बाजपेयी, डीन (प्लानिंग एंड डेवलपमेंट) प्रो.जी डी रामटेककर, डीन (एकेडमिक्स) प्रो. एस गुप्ता, एनआईटी रायपुर के रजिस्ट्रार प्रो.एन डी लोंढे और जन्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के संचालन प्रमुख राजेश पी मोदगेकर, वीपी-बिजनेस सुधीर झा मौजूद रहे।

इस सेंटर को अत्याधुनिक रोबोटिक सिस्टम और एआई-संचालित अनुप्रयोगों के विकास के लिए एक सहयोगी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में कुशल कार्यबल बनाने का द्वार भी खोलेगी। यह साझेदारी उद्योग-एकीकृत शिक्षा और अनुप्रयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एनआईटी रायपुर की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, और जन्यु टेक्नोलॉजीज को भविष्य के इंजीनियरों को कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार करती है। इस सहयोग से रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि, औद्योगिक नवाचार का समर्थन और वैश्विक रोबोटिक्स और ऑटोमेशन परिदृश्य में भारत के नेतृत्व में योगदान मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ बना जीएसटी संग्रह में अग्रणी राज्य

रायपुर। अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ ने 4,135 करोड़ का जीएसटी संग्रहण कर देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपनी जगह बनाई है। जीएसटी संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ ने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संसाधनों से भरपूर झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। राज्य में इस आर्थिक प्रगति को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग क्षेत्र में किए गए सशक्त सुधारों का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बीते 15 महीनों में राज्य सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए हैं, जिनसे निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिला है । गैर-जरूरी और बाधक कानूनों की समाप्ति,सभी जरूरी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता,पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस की बाध्यता को समाप्त करना और उद्योगों की स्थापना के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है। इन सभी पहल से राज्य में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है।

कलेक्टर और एसएसपी ने ली 'लॉ एंड ऑर्डर' को लेकर मातहतों की बैठक

शहर सत्ता/रायपुर। कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में आज कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक ली। कलेक्टर डॉ. सिंह ने सुशासन तिहार के अंतर्गत पुलिस विभाग में लंबित मामलों की जानकारी ली और जल्द निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस और राजस्व अमले को समन्वय बनाकर कार्य करने कहा। कलेक्टर डॉ. सिंह ने अवैध शराब, अवैध खनन और अवैध परिवहन पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसडीएम, तहसीलदार और समस्त पुलिस अधिकारी अपने इलाकों में भ्रमण करें और सूचना तंत्र मजबूत रखें। आसामजिक तत्वों पर निगरानी बनाए रखें और कोई भी घटना होने पर तुंरत सुचना दें।

एसएसपी डॉ. लाल उम्मीद सिंह ने सभी थानेदार से अपने थाना क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त करने और कोई भी घटना होने पर तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए। बैठक में रायपुर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर, श्रीमती निधि साहू, एडीएम देवेंद्र पटेल, एसडीएम, एडिश्नल एसपी एवं समस्त पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

सुशासन तिहार : संवाद से समाधान का तीसरा चरण 5 मई से 31 तक

शहर सत्ता/रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर की तैयारी के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान डॉ. सिंह ने जिले में अब तक प्राप्त सभी आवेदनों की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष बचे आवेदनों का निराकरण आज शाम तक शत प्रतिशत किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि समाधान शिविर के माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाना प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कल से शुरू हो रहे समाधान शिविर में समय पर उपस्थित रहें और शिविर की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने हेतु प्रचार-प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार राज्य में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसका तृतीय चरण 5 मई से 31 मई 2025 तक चलेगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न जनसेवा गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।

हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट जनता को सुविधापूर्ण और निर्धारित समय में लगाने रोड मैप तैयार

हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के लिए हाई लेवल मीटिंग

शहर सत्ता/रायपुर। नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन के सेमिनार कक्ष में विगत दिवस परिवहन सचिव सह परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश तथा अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर की अध्यक्षता में राज्य के समस्त जिला स्तरीय परिवहन अधिकारी सहित हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के लिए अनुबंधित कंपनियों के साथ हाई लेवल बैठक ली गई। बैठक में जनता को आ रही समस्याओं के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा कर इनके निराकरण हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए ।

बैठक में जानकारी दी गयी कि राज्य में 01 अप्रैल 2019 से पहले के लगभग 50 लाख से अधिक पंजीकृत वाहन हैं एवं लगभग 03 लाख के करीब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के ऑर्डर प्राप्त हो चुके है। फिटमेंट की गति बढ़ाने के लिये प्रत्येक जिला स्तर पर वाहनों की संख्या के आधार पर अनुबंधित कंपनियों के फिटमेंट सेंटरों की संख्या में वृद्धि करने तथा हर जिले में जिला स्तरीय परिवहन अधिकारी को कंपनियों के साथ कैम्प टीम बनाने के निर्देश दिये गए। जिले के विभिन्न स्थानों पर कैम्प लगा कर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के नियमानुसार ऑर्डर लेंगे तथा आवश्यकतानुसार नम्बर अपडेट किये जायेंगे। बैठक में निर्देशित किया गया कि दूरस्थ जिलो में दूसरे दिन तक तथा अन्य जिलों में उसी दिन अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट फिट किये जाएं।

बैठक में अनुबंधित कंपनियों को सभी जिलो में वाहनों की संख्या के अनुसार हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट बनाने वाली मशीनों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिये गए हैं ताकि जल्द से जल्द हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट बनें व नियत समय में संबंधित स्थान पर प्लेट पहुंचने के साथ फिटमेंट किया जा सकें। इसके अलावा यह भी निर्देशित किया गया कि हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के लिए ऑर्डर करने पर 15 दिनों से अधिक की वेटिंग न हो, प्रत्येक जिलों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाए और मोबाईल नम्बर सार्वजनिक किये जाएं। कार्यों में तीव्रता व समन्वय लाते हुए 03 महीने की समयावधि में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट फिटमेंट का लक्ष्य रखा गया है।

टारगेट पूरा करने जिलेवार टीम गठित

रायपुर में 05 टीम, धमतरी में 04 टीम, महासमुंद में 04 टीम,दुर्ग- 08 टीम ,कवर्धा-02 टीम,बिलासपुर-06 टीम,जांजगीर चम्पा-03 टीम,कोरबा-05 टीम, रायगढ़-06 टीम,जशपुर- 03 टीम,अम्बिकापुर -04 टीम,कोरिया-03 टीम,जगदलपुर-03 टीम, दंतेवाड़ा-02 टीम,कांकेर-03 टीम, बलौदाबाजार-03 टीम तथा गरियाबंद, बालोद व बेमेतरा में 02-02 टीम एवं अन्य जिलों में 01-01 कैम्प/मोबाईल टीम बनाने के निर्देश दिये गए है।

किसे सुनाएं CHOLLYWOOD की दर्द भरी दास्तान...

छॉलीवुड में नहीं हैं CINTAA, WIFPA, IMPPA जैसी संस्थाएँ

दैहिक, मानसिक और आर्थिक शोषण की पीड़ा झेल रहे लोगों को नहीं मिल रहा सही प्लेटफार्म

फिल्मों की चमक धमक के पीछे छुपी होती हैं कई घिनौनी सच्चाई। शूटिंग के दौरान महिलाओं, क्रू मेंबर्स और कलाकारों समेत टेक्निशियंस का शोषण करने वालों के खिलाफ शिकायतों और कार्रवाई के लिए कोई मजबूत यूनियन, संगठन नहीं है। सहीं प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से छत्तीसगढ़िया कलाकार और अन्य दैहिक, मानसिक और आर्थिक शोषण के शिकार हो रहे हैं। **शहर सत्ता के कला समीक्षक पुरन किरी** को ऐसी कई पीड़ित अभिनेत्रियों, टेक्निशियंस और क्रू मेंबर्स का सन्देश, आ चूका है जिन्हें प्रताड़ित करने वाले निर्माता, निर्देशक, फिल्म प्रोडक्शन हॉउस के मालिकों ने अपने आचरण से आहत किया है।

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री यानी छॉलीवुड आज तेजी से बढ़ रही है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में इस उभरती इंडस्ट्री को सलाम किया जा रहा है। हर तरफ छत्तीसगढ़ी फिल्मों की सराहना हो रही है, नई कहानियाँ, नए चेहरे और नई उमंग लेकर यह फिल्म उद्योग बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है।

यहां काम कर रहे कई कलाकारों और तकनीकी कर्मियों को आज भी तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं किसी कलाकार की मेहनत की कमाई डूब जाती है तो कहीं किसी क्रू मेंबर का एक्सीडेंट होने पर कोई बीमा या हर्जाना की मदद नहीं मिलती। छोटे कलाकारों से बिना अनुबंध के काम लिया जाता है, स्पॉट बॉयज से अतिरिक्त काम करवाकर भी उन्हें अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाता। कई बार कलाकारों पर अनुचित समझौते (compromise) के लिए भी दबाव डाला जाता है। मुंबई जैसी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कलाकारों और क्रू के हितों की रक्षा के लिए CINTAA, WIFPA, IMPPA जैसी संस्थाएँ मौजूद हैं। वहाँ के प्रोड्यूसर, कलाकार और टेक्नीशियन अपने-अपने यूनियन से जुड़े होते हैं, जिससे किसी भी विवाद या शोषण की स्थिति में सुनवाई और मदद मिलती है। लेकिन अफसोस की बात है कि छॉलीवुड में अभी तक ऐसा कोई मजबूत संगठन या यूनियन नहीं बना है जो कलाकारों, स्पॉट बॉयज, तकनीकी कर्मचारियों और छोटे निर्माताओं की रक्षा कर सके। प्रोड्यूसर्स के लिए भले ही कुछ संगठनात्मक प्रयास हुए हैं, मगर कलाकारों और क्रू के लिए एक समर्पित संस्था का न होना आज एक बड़ी खामियां बन रहा है। समय आ गया है कि छॉलीवुड में भी एक ऐसी संस्था बने, जो सभी कलाकारों और तकनीकी साथियों को एकजुट कर उनके अधिकारों और हितों की रक्षा कर सके। ताकि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री न केवल रचनात्मक दृष्टि से बल्कि व्यवस्थागत रूप से भी एक आदर्श मॉडल बन सके। सवाल है — कौन आगे आएगा इस बदलाव की अलख जगाने?

मुंबई, साउथ या अन्य जगहों पर फिल्म उद्योग के बेहतर विकास में वहां की मजबूत यूनियनों का बड़ा योगदान है। इन यूनियनों के कारण कलाकारों और टेक्नीशियनों को काम के अधिकार, आपसी विवाद निपटारे और सरकारी सहायता का लाभ मिलता है। दुर्भाग्य से हमारे यहां ऐसी गिनी-चुनी संस्थाएं ही हैं जो पंजीकृत लोगों की मदद कर पाती हैं। अब वक्त आ गया है कि छत्तीसगढ़ में भी CCTPA जैसी प्रोड्यूसर संस्था के अलावा निर्देशक, कलाकार, संगीतकार, सिंगर, मेकअपमैन, कैमरामैन, कोरियोग्राफर आदि के लिए अलग-अलग यूनियन बनाई जाएं, ताकि सभी को बेहतर सुविधाएं और विवाद समाधान का प्लेटफॉर्म मिल सके।

संतोष जैन, चेयरमैन छत्तीसगढ़ सिने एंड टीवी प्रोड्यूसर एसोसिएशन

छत्तीसगढ़ के फिल्म तकनीशियन और कलाकारों के हितों के लिए आलाप आर्टिस्ट एसोसिएशन का गठन किया गया, जो जरूरत के समय हरसंभव सहयोग करता रहा है। यह संगठन छोटे-बड़े कलाकारों, निर्माता-निर्देशकों और तकनीशियनों का मजबूत मंच रहा है। हालांकि कलाकारों में एकता की कमी, आपसी मनमुटाव, अविश्वास और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण संगठन के कार्य प्रभावित हुए हैं। आज कलाकारों और कामगारों के शोषण और उनके अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई सामने नहीं आता, और अधिकतर लोग स्वार्थवश चुप्पी साधे रहते हैं। आलाप आर्टिस्ट एसोसिएशन इस स्थिति को बदलने और कलाकारों को एकजुट कर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए फिर से प्रतिबद्ध है।

प्रदीप सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, आलाप आर्टिस्ट एसोसिएशन

आलाप आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना 2006 में कलाकारों के हितों की रक्षा के लिए हुई। इसने फिल्म टेक्नीशियन से लेकर स्पॉट बॉय तक सभी के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। संस्कृति विभाग में अधिकतम कलाकारों को स्टेज शो दिलाने, विषम परिस्थितियों में आर्थिक सहायता देने और छत्तीसगढ़ी भाषा में दूरदर्शन प्रसारण शुरू कराने में अहम भूमिका निभाई। कलाकारों को एग्रीमेंट के लिए जागरूक किया गया। एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ी फिल्मों को टॉकीजों में प्राथमिकता दिलाने और फिल्म विकास निगम बनाने जैसी कई मांगों को सरकार तक पहुंचाया। पिछले कुछ वर्षों से एसोसिएशन निष्क्रिय है, जिसे फिर से सक्रिय करना जरूरी है ताकि कलाकारों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

अनुमोद राजवैद्य, महासचिव, आलाप आर्टिस्ट एसोसिएशन

CCTPA (छत्तीसगढ़ सिने एवं टेलीविजन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन) छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माताओं का संगठन है, जो 2011 से सक्रिय है। संगठन ने संघर्ष कर छत्तीसगढ़ी फिल्मों को मल्टीप्लेक्स में जगह दिलाई है, जिससे आज छत्तीसगढ़ी सिनेमा प्रमुखता से प्रदर्शित हो रहा है।

मनोज वर्मा, सचिव छत्तीसगढ़ सिने एवं टेलीविजन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन

बेमिसाल मिसाल हैं

भारती वर्मा

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ की बहुआयामी प्रतिभा भारती वर्मा को सामाजिक सुधारों और फिल्म निर्माण—दोनों ही क्षेत्रों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है। वे न केवल छत्तीसगढ़ की पहली महिला फिल्म निर्देशक हैं, बल्कि एक सक्रिय समाजसेविका भी हैं, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण, आदिवासी अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और बाल शोषण जैसे मुद्दों पर लंबी लड़ाई लड़ी है।

फिल्म इंडस्ट्रीज में आमतौर पर अभिनेत्रियां हीरोइन बनने ही आती हैं। लेकिन हमारे छालीवुड में एक ऐसी भी शख्सियत हैं जो फिल्म निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में एक पहचान बन गईं हैं। पुरुष प्रधान छालीवुड इंडस्ट्रीज में महिला सशक्तिकरण की एकमात्र महिला फिल्म निर्माता 'भारती वर्मा' बेमिसाल 'मिसाल' हैं। जिस शिद्दत से वो अपनी घरु जिम्मेदारी निभाती हैं, उसी ऊर्जा से वो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी शिनाख्त भी बनाने में कामयाब हुई हैं। भारती वर्मा छत्तीसगढ़ की पहली महिला फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और समाजसेवी हैं।

सामाजिक सुधारों में योगदान

भारती वर्मा ने बीते दो दशकों से अधिक समय से समाज सुधार के क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने झुग्गी बस्तियों और आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में काम किया। वे 'जीवेश फाउंडेशन' की संस्थापक हैं, जो सैनिटरी नैपकिन के उपयोग पर जागरूकता, लैंगिक समानता, और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक व कानूनी सहायता प्रदान करता है। कई हरित आंदोलनों में हिस्सा लिया है, जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में हजारों पौधे लगाए गए। मीडिया में सक्रिय रहते हुए वे पिछले 6 वर्षों से महिला सशक्तिकरण को लेकर व्यापक जनजागृति फैला रही हैं।

सामाजिक मुद्दों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ती हैं उनकी फ़िल्में

भारती वर्मा को छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग 'छॉलीवुड' की पहली महिला फिल्म निर्देशक माना जाता है। उन्होंने इस क्षेत्र को नई पहचान दिलाई है। उनके निर्देशन में बनी फिल्में सामाजिक मुद्दों को स्थानीय संस्कृति के साथ जोड़कर पेश करती हैं और नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करती हैं।

शहरसत्ता के कला समीक्षक पूरन किरी की प्रस्तुति

पुरस्कार और सम्मान

- **IBC24 नारी शक्ति सम्मान (2025):** उन्हें "छत्तीसगढ़ की पहली महिला निर्देशक" और "छत्तीसगढ़ी सिनेमा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने" के लिए सम्मानित किया गया।
- **उद्योग सम्मान:** टाइम्स ऑफ इंडिया और स्थानीय मीडिया उन्हें "लोकप्रिय निर्देशक" के रूप में पहचानते हैं, जो सिनेमा के ज़रिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं।

गोल्डन ड्रीम्स प्रोडक्शन

भारती वर्मा की प्रोडक्शन कंपनी Golden Dreams Productions छत्तीसगढ़ी, हिंदी और फ्रेंच फिल्मों का निर्माण करती है। यह कंपनी ना केवल उनकी रचनात्मकता का प्लेटफॉर्म है, बल्कि नए कलाकारों और कहानियों को सामने लाने का माध्यम भी है।

नितिन ग्वाला

संघर्ष, समर्पण और सफलता की कहानी

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के नितिन ग्वाला ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मुंबई में एक्टिंग स्कूल से की, जहां उन्होंने अभिनय की बारीकियों को सीखा और खुद को एक सशक्त कलाकार के रूप में तराशा। एक्टिंग की ट्रेनिंग के बाद संघर्षों का दौर शुरू हुआ, जो लगातार कई सालों तक चला। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाई, जो दो साल तक अटकी रही, लेकिन आखिरकार 2016 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई।

इसके बाद फिर से संघर्षों का सिलसिला जारी रहा। नितिन ने मुंबई में छोटे-छोटे किरदार किए और कुछ लघु फिल्मों में भी काम किया, हालांकि वे रिलीज नहीं हो पाईं। 2022 में नितिन ने 'माया 3' बनाई, जिसने उनकी किस्मत को नया मोड़ दिया। इसके बाद उन्हें 'MCB 2', 'जानकी', लॉकडाउन के दौरान 'माया', और फिर 'MCB 3' जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इन प्रोजेक्ट्स ने उनके करियर को मजबूती दी और अब उनके पास 2025 के लिए भी कई नए प्रोजेक्ट्स हैं।

नितिन ने 2021 में दो वेब सीरीज 'खिचड़ी हो गई जिंदगी' और 'लाल खदान' में भी शानदार काम किया, जिसने उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी पहचान दिलाई। इसके अलावा वे 2013 से 2022 तक दस साल तक लगातार सिनेमा चलाते रहे। 2017 से नितिन छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को मुंबई में आगे बढ़ा रहे हैं। वे सेंसर, फिल्म डाउनलोडिंग और स्टूडियो वर्क जैसी कई जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहे हैं।

अब तक नितिन ने 'ग्वाला फिल्म्स' के बैनर तले दो फिल्में—'माया के मंदिर' और 'माया 3'—प्रोड्यूस की हैं। आज नितिन ग्वाला छत्तीसगढ़ सिनेमा का एक जाना-माना नाम हैं और लगातार अपने काम से नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।

संवाद से समाधान तक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चल रहा सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासकीय योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बन रहा है। 8 अप्रैल से 31 मई 2025 तक तीन चरणों में आयोजित यह अभियान पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसंवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य शासन को जन-केंद्रित बनाना, जन सरोकार, जन विश्वास को मजबूत करना और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करना है। पहले चरण में जनता जनार्दन से उनकी समस्याओं और मांगों के संबंध में 8 से 11 अप्रैल तक समाधान पेटी, ऑनलाइन पोर्टल और शिविर के माध्यम से आवेदन एकत्र प्राप्त किये गए। सुशासन तिहार के पहले चरण में मिले 40 लाख 94 हजार 495 आवेदनों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है, जिसमें मांग से संबंधित 40 लाख 12 हजार 746 आवेदन और शिकायत से संबंधित मात्र 81 हजार 749 आवेदन शामिल हैं। द्वितीय चरण में इन आवेदनों का जिला प्रशासन द्वारा तत्परता से निराकरण किया जा रहा है, जबकि तृतीय चरण में 5 से 31 मई तक समाधान शिविरों में मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधि जनता से रूबरू होंगे। यह अभियान न केवल समस्याओं का समाधान कर रहा है, बल्कि राज्य के मैदानी इलाके से लेकर बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जनता का विश्वास जीत रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्पष्ट और व्यापक हैं। जनता की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण, शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करना और जनता-शासन के बीच संवाद का सेतु बनाना। विशेष रूप से सुकमा, बीजापुर नारायणपुर, दंतेवाड़ा जिले के सुदूर क्षेत्रों में, जहां प्रशासन की पहुंच सीमित थी, यह अभियान जनता की आवाज को न केवल सुन रहा है, बल्कि त्वरित कार्रवाई के माध्यम से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।

श्रमिक कार्ड मिलने से फगिनी और डामिन बाई के चेहरे खिले

सुशासन तिहार के तहत अपने आवेदनों के त्वरित निराकरण होने पर बालोद जिले के ग्राम करहीभदर की फगिनी बाई और डामिन बाई के चेहरे खिल उठे हैं। दोनो ही महिलाओं की जिंदगी मेहनत और उम्मीदों के इर्द-गिर्द घूमती थी। वे अपने गांव और आसपास के गांव में एक श्रमिक के रूप मे मजदूरी करती हैं। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए उनके पास जरूरी श्रमिक कार्ड नहीं था। उन्होंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन जानकारी की कमी से उनका यह काम अधूरा ही रह गया था। लेकिन इस बार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल "सुशासन तिहार 2025" ने उनकी इस समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी से हो गया है। इस अभियान के तहत उनके श्रमिक कार्ड के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई हुई और अपने श्रमिक पंजीयन को देख, उनके चेहरों पर मुस्कान छा गई है।

सुशासन तिहार में भटगांव को मिला बड़ा तोहफा

जनहित को सर्वोपरि रखने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासन नीति का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। सुशासन तिहार के दौरान आम नागरिकों की लंबे समय से मांग को देखते हुए, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश के परिपालन में जिला प्रशासन सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा भटगांववासियों को बड़ी सौगात दी है। अब हर गुरुवार को भटगांव तहसील कार्यालय में एसडीएम लिंक कोर्ट लगेगा, जिससे लोगों को राजस्व मामलों के लिए अब बिलाईगढ़, सारंगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ डॉ. कन्नौजे द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ का न्यायालय अब प्रत्येक गुरुवार को अस्थाई रूप से तहसील कार्यालय भटगांव में लगेगा। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। इस लिंक कोर्ट से सरसीवां और भटगांव तहसील से संबंधित राजस्व, दाण्डिक और समस्त न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई और त्वरित निपटारा संभव हो सकेगा। इसके जरिए प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी और न्याय के लिए आमजन की पहुंच आसान होगी।

स्ट्रीट लाइट से रोशन हुआ पूरा मोहल्ला

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप शासन द्वारा जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए 'सुशासन तिहार' के माध्यम से आमजन की आवाज को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी दिशा में कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 08 के निवासी श्री बोधन दास की एक महत्वपूर्ण समस्या का शीघ्र निराकरण किया गया, जिससे न केवल उन्हें राहत मिली, बल्कि अन्य नागरिकों को भी बेहतर सुविधा का लाभ मिला। श्री बोधन दास ने अपने वार्ड में लंबे समय से खराब या अनुपलब्ध स्ट्रीट लाइट की समस्या को देखते हुए 'सुशासन तिहार' कार्यक्रम के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया था। उनके आवेदन पर नगर पंचायत प्रशासन ने तत्परता दिखाई और शीघ्र कार्यवाही करते हुए उनके क्षेत्र में नई स्ट्रीट लाइटें स्थापित कर दीं। इस कार्य के पूर्ण होने से वार्ड क्रमांक 08 में अब रात्रिकालीन सुरक्षा और आवागमन में सुविधा मिली है। क्षेत्रवासियों ने नगर पंचायत प्रशासन और शासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब मोहल्ले में अंधेरा नहीं रहता, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को रात में बाहर निकलने में आसानी हुई है।

पुश्तैनी भूमि पर फौती नामांतरण से लोकनाथ को मिला अधिकार

'सुशासन तिहार' के अंतर्गत महासमुंद जिले में नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य न केवल शासन की पहुंच को आमजन तक सुनिश्चित करना है, बल्कि वर्षों से लंबित जनसमस्याओं का समाधान भी सुलभ रूप से प्रदान करना है। इसी क्रम में बसना विकासखंड के ग्राम देवरापाल निवासी श्री लोकनाथ को फौती प्रक्रिया पूरी कर उनकी पुश्तैनी भूमि का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। सुशासन तिहार के प्रथम चरण में श्री लोकनाथ, पिता स्वर्गीय कृष्णप्रसाद ने ग्राम देवरापाल पूर्व में उनके पिता श्री कृष्णचंद्र के नाम दर्ज भूमि के नामांतरण के लिए आवेदन दिया था। उनके निधन के उपरांत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की भूमि अधिकार योजना के तहत, विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए जमीन को लोकनाथ के नाम स्थानांतरित किया गया। बसना तहसीलदार ने मौके पर जाकर फौती की प्रक्रिया पूरी करवाई, जिसमें भूमि की वास्तविक स्थिति, कब्जा और सीमाएं जांची जाती हैं। उसके बाद जमीन का सीमांकन कराया गया। फौती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही श्री लोकनाथ को संबंधित खसरा और बी-वन दस्तावेज विधिवत सौंपे गए। अपनी पुश्तैनी भूमि का अधिकार प्राप्त होने पर श्री लोकनाथ भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि यह वह क्षण था, जिसका उन्हें वर्षों से इंतज़ार था। लंबे समय तक चली प्रतीक्षा और निरंतर प्रयासों के बाद जब उन्हें अपने हक का प्रमाण पत्र मिला, तो उनकी आँखें भर आईं।

भारतमाला प्रोजेक्ट

भ्रष्टाचार की माला पहनने वाले 5 IAS की बढ़ेगी तकलीफ

- रायपुर और रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में भी योजना को पलीता लगाने वाले मालामाल
- EOW के बाद ED की एंट्री, एफआईआर के साथ जांच रिपोर्ट की गई है तलब
- भारतमाला प्रोजेक्ट में फर्जी बेटी बनाकर दे दिया मठ की जमीन का मुआवजा

एसडीएम निर्भय साहू

कोरबा डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे

जमीन दलाल हरमीत खनूजा

उमा तिवारी

उमा के पति केदार तिवारी

विजय जैन

विकास यादव/रायपुर

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन मुआवजा के नाम पर छत्तीसगढ़ में कई सौ करोड़ के घोटाले का राजफाश होने को है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की इस योजना और सरकारी खजाने को पलीता लगाने वाले धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। हालांकि अभी तक छत्तीसगढ़ के करीब 11 जिलों से होकर गुजरने वाली इस भारतमाला को भ्रष्टाचार की माला पहनने वाले सिर्फ छुटभय्ये अधिकारी और चंद लोग ही EOW-ACB के शिकंजे में है। नामालूम वजहों से क्यों अब तक केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे CBI की एंट्री नहीं की गई है यह समझ से परे है। बताते हैं कि एक ही तहसील में 300 करोड़ से ऊपर का घोटाला सामने आ रहा है। ऐसे में रायगढ़ समेत अन्य जिलों में क्या खेला हुआ और किनकी शाह में किया गया इसका जवाब अब ED भी खोजेगी। केंद्रीय जांच के बाद यह सम्भावना जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ के 5 IAS अधिकारी भी इसकी जद में आएंगे। इसमें रायपुर, कोरबा और रायगढ़ के तत्कालीन कलेक्टर हैं।

अधिग्रहण नियम क्या है?

अधिग्रहण नियमों के अनुसार, गांवों में 500 वर्गमीटर से कम जमीन है तो उसका मुआवजा ज्यादा मिलता है। जमीन 500 वर्गमीटर से ज्यादा है तो पैसा कम मिलता है। उदाहरण के तौर पर एक एकड़ जमीन का मुआवजा 20 लाख होगा। इसे टुकडों में बांटकर 500 वर्गमीटर से कम कर दिया जाए तो मुआवजा 1 करोड़ हो जाएगा।

शहर सत्ता/रायपुर। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापट्नम एक्सप्रेस वे में हुए 300 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार की फाइलों के पन्ने एक के बाद एक खुलने लगे हैं। इस भ्रष्टाचार की जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। इस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। भ्रष्टाचार यहां तक हुआ कि प्रोजेक्ट के तहत आ रही मठ की जमीन का करोड़ों का मुआवजा एक महिला को फर्जी बेटी बनाकर दे दिया गया। जैतूसाव मठ को जमीन के मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ 37 लाख की मुआवजा राशि दी जानी थी। यह पैसा उमा तिवारी को दे दिया गया जबकि उमा तिवारी का उस मठ मंदिर ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं था। मामला ये था कि विश्वनाथ पांडे ने 1972 में महंत लक्ष्मीनारायण दास से जमीन खरीदी थी। उनकी नकली बेटी बनाकर उमा को मुआवजा दिया गया। कुछ दिनो पहले रायपुर-विशाखापट्टनम तक बन रही (वाइजैग) इकोनॉमिक कॉरिडोर में घोटाले केस में कोरबा डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे को सस्पेंड किया गया था। निर्भय कुमार साहू सहित पांच अधिकारी-कर्मचारियों पर 43 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक राशि की गड़बड़ी का आरोप है। राजस्व विभाग के मुताबिक मुआवजा करीब 29.5 करोड़ का होता है। अभनपुर के ग्राम नायकबांधा और उरला में भू-माफियाओं ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन को छोटे टुकड़ों में काटकर 159 खसरे में बांट दिया। मुआवजा के लिए 80 नए नाम रिकॉर्ड में चढ़ा दिया गया। अभनपुर बेल्ट में 9.38 किलोमीटर के लिए 324 करोड़ मुआवजा राशि निर्धारित की गई। जिसमें से 246 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। वहीं 78 करोड़ रुपए का भुगतान अभी रोक दिया गया है।

अब तक 20 जगहों पर रेड : ईओडब्ल्यू ने अलग अलग शहरों में 20 जगह पर छापामार कार्रवाई की है। EOW ने प्रदेश के रायपुर,दुर्ग,बिलासपुर,महासमुंद में 20 अधिकारियों के यहां कार्रवाई की। इनमें SDM, तहसीलदार, पटवारी और राजस्व निरीक्षक समेत राजस्व विभाग के कई अधिकारियों के ठिकानों पर जांच कर दस्तावेजों की जब्त किया गया है।

इन 11 जिलों में होगी जांच

रायपुर
धमतरी
कांकेर
कोंडागांव
कोरबा
रायगढ़
जशपुर
राजनांदगांव
दुर्ग
बिलासपुर
जांजगीर-चांपा

सबसे पहले बीजेपी नेता ने उठाया था मुद्दा फिर साध लिया मौन

भारतमाला घोटाले की पहली शिकायत चंपू भैया ने की थी। वर्ष 2021 में बाकायदा पूर्व मंत्री और विधायक, सांसद रहे बीजेपी नेता चंद्रशेखर साहू ने इस घोटाले का राजफाश किया था। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस भी लेकर मिडिया से चर्चा की थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने लंबी ख़ामोशी अख्तियार कर ली। प्रेस वार्ता में चंद्रशेखर साहू ने बताया था कि भारत माला सड़क निर्माण और रायपुर-विशाखापत्तनम कॉरिडोर निर्माण के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा दोनों परियोजनाओं के लिए भू अर्जन एवं भूस्वामी को मुआवजा वितरण का कार्य SDM (अनुविभागीय अधिकारी) को सौंपा गया है। इसके तहत अब तक अभनपुर तहसील में 780 करोड़ मुआवजा सैंक्शन हो चुका है और लगभग 600 करोड़ की मुआवजा राशि बांटी भी जा चुकी है।

भारतमाला : भू-अर्जन प्रक्रिया में अनियमितता की संभागायुक्त जांच शुरू

15 मई 2025 को शाम 5:30 बजे तक कर सकते हैं दावा आपत्ति

शहर सत्ता/रायपुर। भारतमाला परियोजना सहित 1 जनवरी 2019 के पश्चात रायपुर संभाग के अंतर्गत जिला रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद एवं बलौदाबाजार-भाटापारा में शासकीय व गैर-शासकीय परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण में हुई अनियमितताओं की संभागायुक्त द्वारा जांच की जा रही है। इस संबंध में अधिग्रहित भूमि की सूची का प्रकाशन आयुक्त कार्यालय रायपुर संभाग, रायपुर की सूचना पटल पर एवं वेबसाइट www.raipur.gov.in एवं संबंधित जिलों के वेबसाइट, कलेक्टर कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत एवं पंजीयक कार्यालयों के सूचना पटल पर किया गया है।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त अधिग्रहण प्रकरणों में की गई प्रक्रिया, मुआवजा निर्धारण या वितरण में किसी प्रकार की आपत्ति या शिकायत हो, तो वे अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा प्रमाणिक दस्तावेजों सहित दिनांक 15.05.2025 को संध्या 5:30 बजे तक संबंधित जिला कार्यालय या संभागीय आयुक्त कार्यालय, रायपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं।

भू-अर्जन की जानकारी जिले के वेबसाईट में अपलोड

जिले के भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किए गए भू-अर्जन की जानकारी रायपुर जिले की वेबसाईट में अपलोड किया गया है। इसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अभनपुर एवं आरंग से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र की जानकारी पत्र के साथ संलग्न है। अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने कहा कि भू-अर्जन में आम व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार आम व्यक्ति को शिकायत हो तो संबंधित एसडीएम अभनपुर एवं आरंग और भू-अर्जन अधिकारी-अभनपुर एवं आरंग कार्यालय में अपनी दावा आपत्ति 15 मई 2025 तक दर्ज करवा सकते है।

जांच के मुख्य बिंदु

- अधिक मुआवजा प्राप्त करने की दृष्टि से मूल खसरे को छोटे-छोटे भूखंडों में कृत्रिम रूप से विभाजित कर मुआवजा प्रकरण तैयार किया जाना।
- भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी होने के बाद किए गए हस्तांतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन, नवीन निर्माण आदि को मुआवजा में शामिल किया जाना।
- पूर्व तिथि से फर्जी नामांतरण या बंटवारा प्रकरण बनाकर मुआवजा प्राप्त करना।
- मुआवजा पत्रक बनाते समय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का सही विवरण प्रस्तुत न करना।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.), मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-22683361, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी।